

[2023] 6 एस. सी. आर 1055

नारायण चेतनराम चौधरी

वी.

महाराष्ट्र राज्य

2018 की आपराधिक विविध याचिका संख्या 157334

में।

पुनरीक्षण याचिका (आपराधिक) सं। 1139-1140 2000 का

में।

(आपराधिक अपील सं। 25-26 2000 का)

27 मार्च, 2023

[के. एम. जोसेफ, अनिरुद्ध बोस और

ऋषिकेश रॉय, जे. जे.]

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015। 9 , 94 – किशोरता-आवेदक का निर्धारण, साथ में दो अन्य साथियों के साथ मिलकर पाँच महिलाओं और दो बच्चों की हत्या कर दी थी-उन पर अपराध करने के लिए मुकदमा चलाया गया था। 302 , 342 , 397 , 449 आई. पी. सी. के आर/डब्ल्यू 120 वी और 34-ट्रायल कोर्ट ने अपीलार्थी को मौत की सजा सुनाई-दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश दोनों की पुष्टि उच्च न्यायालय ने की-सुप्रीम कोर्ट ने उक्त फैसले के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा की गई अपील को खारिज कर दिया-अपीलार्थी द्वारा दायर समीक्षा याचिका को भी खारिज कर दिया गया-अपीलार्थी (28 साल से अधिक समय से हिरासत में) वर्तमान में दायर की गई

एस के तहत आवेदन। 9 (2) 2015 के अधिनियम के अनुसार, उच्चतम न्यायालय से यह अभिनिर्धारित करने का अनुरोध करते हुए कि आवेदक की तिथि पर वह किशोर था

अपराध करना-2019 में आदेश द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को मुख्य जिला और सत्रों को भेज दिया

न्यायाधीश (पूछताछ न्यायाधीश) आवेदक की किशोरता के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए-जांच न्यायाधीश ने किशोरता के लिए आवेदक के दावे को कायम रखते हुए अपनी रिपोर्ट दी-आयोजित: विभिन्न दस्तावेजों की जांच करने पर, यह पाया गया कि आवेदक का मूल नाम 'निरनाराम' था और आवेदक ने यह स्थापित करने के लिए अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाई कि यह वही है जिसे 'नारायण' के रूप में मुकदमा चलाया गया है और दोषी ठहराया गया है-अब, जांच न्यायाधीश द्वारा अपनाए गए पाठ्यक्रम पर विचार करते हुए, एस। 9 (2) 2015 के अधिनियम में 1973 के संहिता और साक्ष्य अधिनियम, 1872 में निर्धारित परीक्षण प्रक्रिया का पालन करने का प्रावधान नहीं है -

विधायिका ने किसी विशिष्ट प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य नहीं किया है

[2023] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

किशोरता निर्धारित करने के लिए जांच करने के लिए न्यायालय द्वारा

2015 के अधिनियम के तहत दावेदार-इसलिए, न्यायालय इसका प्रारूप तैयार कर सकता है इस मामले में जांच करने की अपनी प्रक्रिया-इसमें कोई त्रुटि नहीं है।

जांच न्यायाधीश द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया

तत्काल मामला-जहाँ तक जन्म तिथि के प्रमाण पत्र का संबंध है,

आवेदक ने स्कूल द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर भरोसा किया है

उसकी उम्र का निर्धारण-उक्त प्रमाण पत्र स्कूल के प्रधानाध्यापक के कार्यालय द्वारा जारी किया गया था-स्कूल के प्राचार्य ने लिखित रूप में बताया गया है कि प्रवेश रजिस्टर की सामग्री है

व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में बनाए रखा गया सामान्य पाठ्यक्रम में

उक्त रजिस्टर 1872 के अधिनियम की धारा 35 में निर्दिष्ट परीक्षण को संतुष्ट करेगा, जो एक प्रासंगिक तथ्य है-इसलिए, स्कूल द्वारा जारी प्रमाण पत्र में परिलक्षित आवेदक की जन्म तिथि को उस अपराध के समय उसकी आयु निर्धारित करने के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया है-उस प्रमाण पत्र के अनुसार, उसकी आयु

अपराध करने का समय 12 वर्ष और 6 महीने का था। इस प्रकार, वह अपराध करने की तारीख को एक बच्चा/किशोर था।

निचली अदालत द्वारा उसे मौत की सजा सुनाने का आदेश पारित किया गया और

बाद में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई और कानून के संचालन द्वारा अमान्य कर दिया गया।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015

- एस। 9 (2) - किशोरता याचिका उठाने का चरण-एक याचिका यू/एस। 9 (2) 2015 के अधिनियम में वैधानिक उपचार पर विचार किया गया है, जिसके लिए याचिका दायर की जा सकती है -

किसी भी स्तर पर उठाया गया-किशोरता याचिका पर, यदि एक रिट याचिका को सीमित रूप से खारिज कर दिया जाता है, तो ऐसा आदेश धाराओं की उप-धारा (2) के तहत किशोरता के लिए याचिका दायर करने के लिए एक आरोपी (या एक दोषी) के विकल्प को बंद नहीं करेगा। 9 2015 का अधिनियम।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015। 9 (2) , 103 - ' जाँच '-जहाँ तक न्यायालय द्वारा जाँच करने की प्रक्रिया का संबंध है। 9 (2) सावधानीपूर्वक निर्धारित नहीं करता है

दंड संहिता में निर्धारित परीक्षण प्रक्रिया का पालन करना

प्रक्रिया 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872-न्यायालय

जाँच करवाकर लेल अपन प्रक्रिया तैयार कऽ सकैत अछि।

आवेदन को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1 . राज्य ने यह दलील दी है कि जांच के समय उन्हें इसे सत्यापित करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं था तथ्य। ऐसे कई दस्तावेज हैं जिनमें निरनाराम नारायण चेतनराम चौधरी बनाम रहे हैं।

महाराष्ट्र राज्य

'सी' के पुत्र के रूप में दिखाया गया है। 2019 में जाँच रिपोर्ट बनाए जाने के बाद, इस न्यायालय की सुनवाई के बाद से काफी समय बीत चुका है।

बात है। राज्य द्वारा यह प्रदर्शित करने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई थी कि जलबसार या किसी अन्य 'सी' में कोई अन्य निरनाराम था। यह एक तथ्य है कि किशोरता के दावेदार को अपना मामला स्थापित करना होता है। लेकिन इस बात की भी सराहना की जानी चाहिए कि 28 साल से अधिक समय तक जेल में रहने वाले मौत की सजा पाए दोषी को अपने स्कूल के रिकॉर्ड और उम्र के अन्य प्रमाणों को फिर से प्राप्त करने में गंभीर सीमाएं होंगी। ऐसी परिस्थितियों में, किसी भी विपरीत साक्ष्य के अभाव में यह न्यायालय प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश, पुणे द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट में इस निष्कर्ष को स्वीकार करता है कि निरनाराम को "नारायण" का दूसरा नाम कहा जाना चाहिए। इस मुद्दे पर इस न्यायालय की राय अलग नहीं होगी, भले ही यह न्यायालय सरपंच के प्रमाण पत्र को अस्वीकार कर दे। वह प्रमाणपत्र आवेदक के नाम के निर्धारण में सहायक भूमिका निभाता है। इसके अलावा, इन सभी दस्तावेजों में, जलबसार को उस गाँव के रूप में दिखाया गया है जहाँ 'सी' और उसका परिवार निवासी थे, और यही वह स्थान था जहाँ से उसे गिरफ्तार किया गया था। इस अदालत की राय में, आवेदक का मूल नाम निरनाराम था और आवेदक ने यह स्थापित करने के लिए अपने हिस्से का दायित्व निभाया है कि यह वही है जिस पर नारायण के रूप में मुकदमा चलाया गया और उसे दोषी ठहराया गया। इस न्यायालय ने इस मुद्दे पर जांच न्यायाधीश के निष्कर्ष को स्वीकार कर लिया। [पैरा 19] [1088-जी-एच; 1089-ए-सी]

2. 2015 अधिनियम की धारा 9 (2) के तहत वर्तमान आवेदन की रखरखाव के संबंध में। आवेदक के मामले में,

इस न्यायालय के समक्ष पहली बार किशोरता याचिका दायर की गई है, हालांकि इस न्यायालय द्वारा उनकी दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखने के खिलाफ उनकी समीक्षा याचिका खारिज होने के बाद। यह एक तथ्य है कि किशोरता याचिका 2013 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 126 में उठाई गई थी और इस रिट याचिका को सीमित रूप से खारिज कर दिया गया था। लेकिन जहां तक वर्तमान आवेदन का संबंध है, यह बर्खास्तगी न्यायिक प्रक्रिया के रूप में कार्य नहीं करेगी। के अनुच्छेद 32 के तहत राहत

संविधान विवेकाधीन प्रकृति का है और उस याचिका को खारिज करने वाला इस न्यायालय का आदेश कारण से समर्थित नहीं है। 2015 के अधिनियम की धारा 9 (2) के तहत एक याचिका में वैधानिक उपचार पर विचार किया गया है,

जिसके लिए किसी भी स्तर पर याचिका दायर की जा सकती है। इस अदालत की राय में, किशोरता याचिका पर, यदि एक रिट याचिका को सीमित रूप से खारिज कर दिया जाता है, तो ऐसा आदेश 2015 के अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) के तहत किशोरता के लिए याचिका दायर करने के लिए एक आरोपी (या एक दोषी) के विकल्प को बंद नहीं करेगा। [पैरा 20,21] [1089-डी-एफ; 1090-डी] [2023] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. इसके बाद यह सवाल आता है कि क्या जांच न्यायाधीश द्वारा अपनाया गया पाठ्यक्रम 2015 के अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में था या नहीं। यह स्पष्ट है कि जांच न्यायाधीश ने आमतौर पर एक तथ्य-निष्कर्ष जांच के रूप में जांच का संचालन किया है आयोजित किया गया और समन परीक्षण की प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। जिन दस्तावेजों पर उन्होंने भरोसा किया था, वे औपचारिक रूप से साबित नहीं हुए थे

वर्तमान मामले में इस न्यायालय द्वारा जिस प्रक्रिया का पालन किया गया है, वह एक प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश, राज्य स्तर पर एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी को एक निश्चित समय सीमा के भीतर जांच करने का निर्देश देना है। जैसा कि इस अदालत ने जांच रिपोर्ट से पाया, जांच न्यायाधीश ने एक पुलिस अधिकारी को निर्देश दिया था कि आवेदक द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों का प्रमाणीकरण और पुलिस अधिकारी द्वारा दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर अपने विचार देने के बाद, उनमें से कुछ में विसंगति पाई गई। इसके बाद, जांच न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई की गई, जिसमें अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व पुलिस महानिदेशक ("डीजीपी") के पद पर आसीन एक अधिकारी द्वारा किया गया। अभियोजन पक्ष और पुलिस दोनों ने जांच न्यायाधीश के समक्ष रिपोर्ट और बयान दायर किया था। जाँचकर्ता न्यायाधीश ने स्वयं अभियोजन पक्ष के साथ-साथ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों पर विचार करते हुए अपना दिमाग लगाया और आवेदक को स्वयं जाँचकर्ता न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया। जाँचकर्ता न्यायाधीश ने उनके सामने दाखिल किए गए दस्तावेजों को प्रदर्शन के रूप में चिह्नित किया था। जाँच करने वाले न्यायाधीश ने डी. जी. पी. और आवेदक का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील के रुख का पता लगाने पर प्रत्येक दस्तावेज़ की जाँच की।

दायर आवेदन में नारायण चेतनराम चौधरी बनाम. महाराष्ट्र राज्य

हमारे सामने, स्कूल रजिस्टर से उद्धरण संलग्न किया गया था जिसमें आवेदक की जन्म तिथि 1 फरवरी 1982 दिखाई गई थी। जाँच न्यायाधीश के समक्ष, इस न्यायालय ने पाया कि आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों के अलावा, स्कूल प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र भी आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बाद वाला स्कूल रजिस्टर के आधार पर जारी किया गया था लेकिन यह प्रमाण पत्र था दिनांक 30 जनवरी 2019। [पारस 25,27] [1092-ए; 1093-एफ-एच; 1094 ए-ई]

4. इस न्यायालय ने जाँच न्यायाधीश द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं पाई। जहाँ तक प्रक्रिया की बात है

न्यायालय द्वारा जाँच करना, इस न्यायालय की राय में 2015 के अधिनियम की धारा 9 (2) 1973 की संहिता और भारतीय संविधान में निर्धारित परीक्षण प्रक्रिया का ईमानदारी से पालन करने का निर्देश नहीं देती है। साक्ष्य अधिनियम, 1872। 2015 के अधिनियम की धारा 103 (2) के अनुसार संहिता का पालन करने की आवश्यकता "जहाँ तक संभव हो" है। द.

इस प्रकार, एक किशोर दावेदार की आयु निर्धारण पर बोर्ड या समिति द्वारा जाँच के लिए समन परीक्षण प्रक्रिया निर्धारित करते समय विधायिका ने न्यायालय द्वारा जाँच के लिए किसी विशिष्ट प्रक्रिया को अनिवार्य नहीं किया है। इसका तात्पर्य यह है कि न्यायालय इस संबंध में जाँच करने के लिए अपनी प्रक्रिया तैयार कर सकता है। जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है, इस न्यायालय ने निर्देश दिया था

प्रथम स्तर पर जाँचकर्ता न्यायाधीश द्वारा की जाने वाली जाँच, जिसके समक्ष आवेदक और अभियोजन पक्ष को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर था। जाँच न्यायाधीश की रिपोर्ट की बाद में हमारे द्वारा जाँच की गई, जिससे दोनों पक्षों को फिर से पर्याप्त अवसर मिला। इस न्यायालय ने स्वयं विद्यालय से मूल प्रवेश रजिस्टर की मांग की है। द. प्रधानाचार्य-विद्यालय के प्रभारी, ने जाँच स्तर पर लिखित में एक बयान दिया था, और जिसका अनुवादित संस्करण दिखाई देता है

जाँच रिपोर्ट के पृष्ठ 311 पर। [पैरा 28] [1094-एफ; 1095-एफ-एच; 1096-ए]

5. विचाराधीन विद्यालय एक सरकारी विद्यालय है। निरनाराम का "जन्म प्रमाण पत्र की तारीख" के कार्यालय द्वारा जारी किया गया है। उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक। यह प्रमाण पत्र राष्ट्रीय प्रतीक वाले राज्य सरकार के लेटरहेड पर जारी किया गया है। स्कूल के प्रधानाचार्य ने लिखित रूप में खुलासा किया है कि प्रवेश रजिस्टर की सामग्री सामान्य व्यवसाय में रखी जाती है। इसलिए, सामान्य रूप से उक्त रजिस्टर [2023] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1872 के अधिनियम की धारा 35 में निर्दिष्ट परीक्षण को संतुष्ट करेगा, जो एक प्रासंगिक तथ्य है। [पैरा 33] [1105-ए-बी]

6. प्रवेश की प्रामाणिकता या वास्तविकता के संबंध में

यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता कि प्रवेश रजिस्टर स्वयं नकली है। जहां तक निरनाराम के नाम का सवाल है, प्रवेश पत्र में रजिस्टर में कोई विसंगति नहीं है। उनका क्रम संख्या 568 है जो उस क्रम में आता है जिसमें रजिस्टर बनाए रखा जाता है और अनुक्रम में होता है।

अन्य प्रविष्टियों में नामों के संबंध में कुछ मामूली विसंगतियों को छोड़कर अन्य छात्रों की प्रवेश प्रविष्टियों के साथ। भले ही

इस न्यायालय को भेजने के लिए रजिस्टर को नए सिरे से सिलवाया गया है और पृष्ठांकन किया गया है, जिससे यह निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि पूरी बात गढ़ी गई है। इसके अलावा, यह प्रदर्शित करने के लिए कोई स्पष्ट सबूत नहीं है कि प्रारंभिक जांच के समय, रजिस्टर बिना सिलाई या बिना पृष्ठांकन के था। इस न्यायालय ने स्वयं रजिस्टर को देखा है और यह काफी पुराना है।

इस प्रकार, यह न्यायालय नारायण चेतनराम चौधरी बनाम से सहमत है। महाराष्ट्र राज्य

7. जहाँ तक आवेदक का संबंध है, स्कूल प्रमाण पत्र में उसकी जन्म तिथि के आधार पर किशोरावस्था का उसका दावा भिन्न नहीं होगा। 1986 अधिनियम, 2000 अधिनियम या 2015 अधिनियम के तहत किशोर, "कानून के साथ संघर्ष में किशोर" या "कानून के साथ संघर्ष में बच्चा" की परिभाषाओं के आधार पर। इस न्यायालय की राय में, उसके किशोर होने या बच्चा होने के दावे को निर्धारित करने की प्रक्रिया को लागू करने के लिए, उस अभ्यास को करने के समय लागू कानून

8. 2015 के अधिनियम के तहत किशोरावस्था के निर्धारण के लिए जन्म प्रमाण पत्र की तारीख मुख्य कारक होनी चाहिए। के मामले में ऋषिपाल सिंह सोलंकी, इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने

इस सिद्धांत को निर्धारित किया कि 2015 अधिनियम की धारा 9 (2) के तहत शुरू की गई जांच उसकी धारा 94 में निहित जांच के समान होगी। इस न्यायालय ने इस विचार को स्वीकार कर लिया। इस न्यायालय ने जन्म प्रमाण पत्र की तारीख का स्रोत मांगा है, जिसमें स्कूल में प्रवेश के समय आवेदक की जन्म तिथि दर्ज की गई थी, जो वर्ष 1986 में थी। जहाँ तक अन्य दस्तावेजों में उल्लिखित जन्म की असंगत तिथियों का संबंध है, उनमें से किसी को भी आयु की प्रक्रिया शुरू करने के लिए ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए।

उक्त कानून की धारा 94 (2) में निर्धारित निर्धारण। एक बार जब आवेदक अपने दायित्व का निर्वहन कर लेता है, तो स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके किशोरावस्था के अपने दावे के समर्थन में, राज्य को किसी भी सम्मोहक के साथ आना पड़ता है

यह दिखाने के लिए विरोधाभासी सबूत कि प्रवेश रजिस्टर में उनकी जन्म तिथि का रिकॉर्ड गलत था। इस मामले में राज्य ने ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं दिया है जो इस तरह के प्रमाण पत्र को अविश्वसनीय या गलत साबित करे। राज्य और शिकायतकर्ता ने मतदाता सूची के अलावा केवल उसके द्वारा प्रकट की गई सामग्री के आधार पर आवेदक के मामले को गलत साबित करने की मांग की है। यहाँ, यह न्यायालय किसी भी अनुमान में शामिल नहीं हो सकता है स्कूल रजिस्टर में प्रविष्टि पर संदेह करना। [2023] 6 एस. सी. आर. में परिलक्षित आवेदक की आयु के आधार का खंडन करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उपरोक्त दस्तावेज़। आयु के प्रमाण के रूप में जन्म तिथि का प्रमाण पत्र क़ानून में ही प्रदान किया गया है, यह न्यायालय

उस पर जाएँ। दूसरा कारक जो इस अदालत के दिमाग में आया है वह यह है कि क्या 12 साल का लड़का इस तरह का वीभत्स अपराध कर सकता है। लेकिन हालांकि यह कारक इस न्यायालय को झकझोर देता है, यह न्यायालय इस न्यायालय की निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए इस प्रकृति की अटकलों को लागू नहीं कर सकता है। इस न्यायालय को जांच न्यायाधीश की रिपोर्ट की जांच करते समय इस कारक को ध्यान में रखने के लिए बाल मनोविज्ञान या अपराध विज्ञान का कोई ज्ञान नहीं है। इसके अलावा, अस्थिरकरण परीक्षण में प्रकट आवेदक की आयु आवेदक की आयु को, जैसा कि उसने दावा किया है, रिपोर्ट में निर्दिष्ट सीमा के भीतर रखती है। उक्त परीक्षण वर्ष 2005 में आयोजित किया गया था, और उनकी आयु 22 से 40 वर्ष की सीमा में निर्धारित की गई थी। यदि यह न्यायालय 2005 में उनकी आयु 22 वर्ष मानता है, तो उनका जन्म वर्ष होगा

1983 की बात है। यह मोटे तौर पर जन्म तिथि के अनुरूप होगा।

प्रवेश रजिस्टर में निहित। [पैरा 41] [1111-जी-एच; 1112 ए-ई]

9. इस न्यायालय के निष्कर्षों और इस न्यायालय द्वारा इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ऊपर बताए गए कारणों के आलोक में, यह न्यायालय जांच न्यायाधीश की रिपोर्ट को स्वीकार करता है। यह न्यायालय घोषणा करता है कि आवेदक की जन्म तिथि जैसा कि राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, जलबसार, तहसील श्री डूंगरगढ़, जिला-बीकानेर, दिनांक 30 जनवरी 2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र में परिलक्षित होती है, जिसकी एक प्रति जांच रिपोर्ट में "आई-2" के रूप में संलग्न की गई है, उस अपराध के समय उसकी आयु निर्धारित करने के लिए स्वीकार की जानी है, जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया है। उस प्रमाण पत्र के अनुसार, अपराध करने के समय उनकी आयु 12 वर्ष और 6 महीने थी। इस प्रकार, वह अपराध करने की तारीख को एक बच्चा/किशोर था जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया है।

2015 के अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में दोषी ठहराया गया। यह निरनाराम की वास्तविक आयु मानी जाएगी, जिन पर नारायण के रूप में मुकदमा चलाया गया और उन्हें दोषी ठहराया गया। वह पहले ही 3 साल से अधिक की कारावास की सजा काट चुका है और कानून के तहत जैसा कि अपराध के समय प्रचलित था और 2015 के अधिनियम के तहत भी, उसे मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है। इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे द्वारा 1994 के सत्र मामले संख्या 462 में उन्हें मौत की सजा सुनाने का आदेश पारित किया गया और बाद में

उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा पुष्टि कानून के संचालन द्वारा अमान्य हो जाएगी।

उसे नारायण चेतनराम चौधरी बनाम के साथ तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य

सुधार गृह से जिसमें वह कैद रहता है, जैसे 2015 के अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उन्हें 28 साल से अधिक समय तक कारावास का सामना करना पड़ा है। 1986 के अधिनियम की धारा 21 में भी काफी हद तक एक ही प्रावधान था -

अधिकतम सजा का प्रश्न जो किशोर न्यायालय द्वारा अपराधी किशोर को दी जा सकती है। इस पर लगी रोक निरोध की अवधि जो बोर्ड द्वारा 2015 के अधिनियम के तहत 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को दी जा सकती है, उस न्यायालय पर भी लागू होगी जिसके समक्ष किशोरता का प्रश्न निर्धारित किया जा रहा है। [पैरा 43] [1113-ई-एच; 1114-ए-सी]

अश्विनी कुमार सक्सेना बनाम। मध्य प्रदेश राज्य (2012) 9 एस. सी. सी. 750 [2012] 10 एस. सी. आर. 540-पर निर्भर था। विरादमल सिंघवी बनाम। आनंद पुरोहित (1988) पूरक एस. सी. सी. 604: [1988] पूरक। एस. सी. आर. 1; सूरजदेव महतो और एक अन्य बनाम बिहार राज्य (2022) 11 एससीसी 800; मोहम्मद। अनवर बनाम। राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (2020) 7 एस. सी. सी. 391; रामदेव

चौहान उर्फ राज नाथ बनाम। असम राज्य (2001) 5 एससीसी 714 [2001] 3 एससीआर 669; संजीव कुमार गुप्ता बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और दूसरा (2019) 12 एस. सी. सी. 370: [2019] 9 एस. सी. आर. 735; पराग भाटी (किशोर) कानूनी अभिभावक के माध्यम से-माँ-रजनी भाटी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और दूसरा (2016) 12 एस. सी. सी. 744: [2016] 2 एससीआर 1089; मनोज उर्फ मोनू उर्फ विशाल चौधरी बनाम। हरियाणा राज्य और एक अन्य (2022) 6 एस. सी. सी. 187; बबलू पासी बनाम। झारखंड राज्य और एक अन्य (2008) 13 एस. सी. सी. 133: [2008] 14 एससीआर 161-प्रतिष्ठित।

मुरारी ठाकुर और एक अन्य वी। बिहार राज्य (2009) 16 एससीसी 256: [2006] 10 पूरक। एस. सी. आर. 988-अच्छा नहीं रहा कानून।

राम विजय सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य 2021 एससीसी ऑन लाइन एससी 142; अबुज़र हुसैन उर्फ गुलाम हुसैन बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य (2012) 10 एससीसी 489: [2012] 9 एससीआर 244; पवन कुमार गुप्ता बनाम। राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (2020) 2 एस. सी. सी. 803 [2020] 1 एस. सी. आर. 69; पवन बनाम। उत्तरांचल राज्य (2009) 15 एससीसी 259: [2009] 3 एस. सी. आर. 468; रविंदर सिंह गोरखी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2006) 5 एस. सी. सी. 584: [2006] 2 पूरक। एस. सी. आर. 615; हरि राम बनाम।

[2023] 6 एस. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राजस्थान और एक अन्य (2009) 13 एस. सी. सी. 211: [2009]

7 एस. सी. आर. 623; अब्दुल रज्जाक बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य

(2015) 15 एस. सी. सी. 637; विनोद कटारा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
प्रदेश 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1204; राम नारायण बनाम।

उत्तर प्रदेश राज्य (2015) 17 एससीसी 699: [2015] 9

एस. सी. आर. 200; उपेंद्र प्रधान बनाम. स्टार्ड ऑफ़ उड़ीसा (2015)

11 एससीसी 124: [2015] 5 एस. सी. आर. 214; अजय कुमार बनाम राज्य

मध्य प्रदेश का (2010) 15 एस. सी. सी. 83; शिव मंगल
सिंह और अन्य बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1989) एस. सी. सी. ऑनलाइन

सभी 605; ऋषिपाल सिंह सोलंकी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य

और अन्य (2022) 8 एससीसी 602; प्रताप सिंह बनाम। की स्थिति

झारखंड और दूसरा (2005) 3 एस. सी. सी. 551: [2005] 1

एस. सी. आर. 1019; जितेंद्र सिंह उर्फ बब्बू सिंह और

एक अन्य वी। उत्तर प्रदेश राज्य (2013) 11 एससीसी 193:

[2013] 13 एस. सी. आर. 764; धरमवीर बनाम। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली)

और दूसरा (2010) 5 एस. सी. सी. 344 [2010] 5 एस. सी. आर. 137;

महेश जोगी बनाम। राजस्थान राज्य (2014) 15 एससीसी

184 [2014] 11 एस. सी. आर. 293; सत्य देव उर्फ भूरे बनाम।

उत्तर प्रदेश राज्य (2020) 10 एस. सी. सी. 555

जम्मू और कश्मीर (अब जम्मू और कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश)

और अन्य वी। शुभम संगरा 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी
1592 ; राजिंदर चंद्र बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य और

एक अन्य (2002) 2 एस. सी. सी. 287-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2012] 10 एससीआर 540

उस पर भरोसा करें

पै

रा 12

[2012] 9 एससीआर 244

संदर्भित किया गया है

पै

रा 12

[2020] 1 एससीआर 69

संदर्भित किया गया है

पै

रा 12

[2006] 10 पूरक। एससीआर 988

अच्छा कानून नहीं है

पै

रा 13

[2009] 3 एससीआर 468

संदर्भित किया गया है

पै

रा 13

[2006] 2 पूरक। एससीआर 615

संदर्भित किया गया है

पै

रा 14

[2001] 3 एससीआर 669

प्रतिष्ठित

पै

रा 14

[1988] पूरक। एससीआर 1

प्रतिष्ठित

पै

रा 14

[2009] 7 एससीआर 623

संदर्भित किया गया है

पै

रा 20

[2015] 9 एससीआर 200

संदर्भित किया गया है

पैरा 20 नारायण चेतनराम चौधरी बनाम। राज्य

महाराष्ट्र

[2015] 5 एससीआर 214

संदर्भित किया गया है

पै

रा 20

[2016] 2 एससीआर 1089

प्रतिष्ठित

पै

रा 32

[2019] 9 एससीआर 735

प्रतिष्ठित

पै

रा 37

[2008] 14 एससीआर 161

प्रतिष्ठित

पै

रा 37

[2005] 1 एससीआर 1019

संदर्भित किया गया है

पै

रा 38

[2013] 13 एससीआर 764

संदर्भित किया गया है

पै

रा 39

[2010] 5 एससीआर 137

संदर्भित किया गया है

रा 39

[2014] 11 एससीआर 293

रा 39

संदर्भित किया गया है

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: अपराधी

समीक्षा याचिका (आपराधिक) संख्या में 2018 की विविध याचिका संख्या 157334। 1139-1140
आपराधिक अपील सं. 2000 में। 25-26 2000 से।

Crl.A.Nos में दिनांकित 05.09.2000 निर्णय और आदेश से। 26

और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का 2000 का 25.

आर. बसंत, Sr.Adv।, विष्णु पी., सुश्री तृषा चंद्रन, सुश्री श्रेया

रस्तोगी, शादान फरासत, एड. आवेदक के लिए।

सचिन पाटिल, सिद्धार्थ धर्माधिकारी, आदित्य अनिरुद्ध पांडे,

भरत बागला, सौरव सिंह, जियो जोसेफ, रिस्वी मुहम्मद, दुर्गेश गुप्ता, ऋषिकेश चिताली, विजय कारी
सिंह, रजत जोसेफ, एड. उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था
अनिरुद्ध बोस, जे।

यह किशोर न्याय की धारा 9 (2) के तहत एक आवेदन है।

(बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 ("2015 अधिनियम") इस न्यायालय से यह
अभिनिर्धारित करने का अनुरोध करता है कि आवेदक, जो अपराध करने के लिए दोषी है।

भारतीय दंड संहिता, 1860 ("1860 संहिता") की धारा 120 बी और 34 के साथ पठित धारा
242,342,397,449 के तहत अपराध अपराध करने की तारीख को एक किशोर था। आवेदक की एक
साथ प्रार्थना इस आधार पर हिरासत से उसकी रिहाई के लिए है कि उसने अधिनियम के तहत अनुमेय
अधिकतम सजा से अधिक की सजा काट ली है। आवेदक को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे द्वारा क्रमशः 19
फरवरी 1998 और 23 फरवरी 1998 के एक फैसले और आदेश द्वारा मौत की सजा सुनाई गई है।

यह आवेदन उस आदेश की समीक्षा के लिए एक याचिका के संबंध में लिया गया है जिसके द्वारा उनकी
दोषसिद्धि और सजा को कायम रखा गया था [2023] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के बाद इस न्यायालय द्वारा आवेदक की पुनर्विचार याचिका भी 24 नवंबर 2000 को खारिज कर दी गई थी। दो अन्य अपराधियों (जीतू और राजू) के साथ आवेदक पर 1860 की संहिता के उपरोक्त प्रावधानों के तहत अपराध करने का मुकदमा चलाया गया था। द.

आवेदक ने मुकदमे या अपीलीय स्तर पर किशोरता की याचिका नहीं उठाई थी। निचली अदालत में कहा गया कि राजू सरकारी गवाह बन गया था और उसे माफी दे दी गई थी। दोषसिद्धि का निर्णय और सजा का आदेश दोनों थे

उच्च न्यायालय द्वारा 22 जुलाई 1999 को आवेदक की अपील में और पुष्टि कार्यवाही में भी पुष्टि की गई। दोषी ठहराए जाने के फैसले और आवेदक द्वारा दिए गए मौत की सजा के आदेश के खिलाफ अपील को इस अदालत ने 5 सितंबर 2000 को खारिज कर दिया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आवेदक का अपराध वीभत्स प्रकृति का है। 26 अगस्त 1994 को, इस अदालत सहित सभी न्यायिक मंचों द्वारा बनाए गए अभियोजन मामले के अनुसार, आवेदक ने दो अन्य साथियों के साथ पांच महिलाओं (जिनमें से एक गर्भवती थी) और दो बच्चों की हत्या कर दी थी। यह अपराध महाराष्ट्र राज्य के पुणे में हुआ था। आवेदक को 5 सितंबर 1994 को उसके गृह गांव से गिरफ्तार किया गया था और वह 28 साल से अधिक समय से हिरासत में है।

नाम निरनाराम है। जाँच रिपोर्ट, जिस पर हम बाद में इस फैसले में चर्चा करेंगे, में इस बात का अवलोकन किया गया है कि पुणे, महाराष्ट्र में लोगों को निरनाराम का उच्चारण करना मुश्किल हो सकता है और पुणे में "निरनाराम" को "नारायण" कहने में उच्चारण की गलती की संभावना। उक्त तहसील पहले चुरू जिले में थी लेकिन वर्ष 2001 में यह बीकानेर जिले के भीतर आई। अपराध की घटना की तिथि 26 अगस्त 1994 है और आवेदक के खिलाफ प्रस्तुत आरोप पत्र में अपराध के समय उसकी आयु लगभग 20 वर्ष बताई गई है। आवेदक का किशोर होने का दावा मुख्य रूप से चेतनराम के बेटे निरनाराम के नाम पर 30 जनवरी 2019 को जारी जन्म तिथि के "प्रमाण पत्र" पर आधारित है। उक्त प्रमाणपत्र प्रधानाचार्य (प्रधानाध्यापक), राजकिया आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, जलबसार, श्री डूंगरगढ़ द्वारा जारी किया गया है। उक्त दस्तावेज़ में, यह दर्ज किया गया है कि निरनाराम का जन्म 1 फरवरी 1982 को हुआ था। 15 अगस्त 2001 को उसी प्राधिकरण द्वारा जारी एक "स्थानांतरण प्रमाण पत्र" में, यह परिलक्षित होता है कि वह 1 अप्रैल 1986 को प्रवेश संख्या 568 के माध्यम से पहली कक्षा में स्कूल में शामिल हुए थे और 15 मई 1989 को तीसरी कक्षा (उत्तीर्ण) से चले गए थे।

नारायण चेतनराम चौधरी बनाम। महाराष्ट्र राज्य [अनिरुद्ध बोस, जे.]

इन प्रमाणपत्रों में परिलक्षित जन्म तिथि तक, आयु

अपराध करने की तारीख को आवेदक 12 वर्ष का होता। वर्ष और 6 महीने। जैसा कि हम पहले ही संकेत दे चुके हैं, आवेदक पर नारायण के रूप में मुकदमा चलाया गया था, न कि निरनाराम के रूप में। इसके अलावा, कुछ अन्य दस्तावेजों में निरनाराम की उम्र उक्त प्रमाण पत्रों में परिलक्षित उम्र से अलग दिखाई गई है। आवेदक के नाम और उसकी उम्र के संबंध में भिन्नता या विसंगतियां वे कारक हैं जिन पर हम विचार करेंगे।

निर्णय और हम इस निर्णय के बाद के पैराग्राफ में इन पहलुओं पर ध्यान देंगे।

3. आरोप पत्र में आरोपी नारायण की उम्र को दिखाया गया था -

20 साल हो जाएँ। हम उच्च न्यायालय के फैसले से पाते हैं कि उक्त आयु (20-22 वर्ष) केवल उस समय आवेदक की ओर से दी गई थी

सुनने के लिए। उच्च न्यायालय ने अपील और मृत्यु संदर्भ में अपने फैसले में आवेदक की उम्र के सवाल का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था। हालाँकि, उस समय किशोरावस्था की दलील नहीं थी। उच्च न्यायालय के फैसले में यह देखा गया कि सजा देने के सवाल पर विचार करते समय घटना के समय आरोपी की उम्र को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

4. आवेदक पहली बार चिकित्सा जांच चाहता था

14 अगस्त 2005 को उनकी उम्र के निर्धारण के लिए, जब जेल महानिरीक्षक, पश्चिमी प्रभाग, पुणे यरवदा केंद्रीय जेल में आवेदक से मिलने गए थे। इसके बाद जेल अधिकारियों द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अनुरोध किया गया और आवेदक को फॉरेंसिक विज्ञान विभाग, बीजे मेडिकल कॉलेज और ससून ले जाया गया। जनरल अस्पताल, पुणे। उक्त संस्थान के फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग द्वारा आयु निर्धारण रिपोर्ट में कहा गया है कि 24 अगस्त 2005 को रोगी की आयु 22 वर्ष से अधिक थी, लेकिन त्रुटि के अंतर सहित 40 वर्ष से कम थी। उक्त रिपोर्ट में कहा गया है: -

" एम.

डी./आयु/198/2005

फॉरेंसिक विज्ञान विभाग

बी. जे. मेडिकल कॉलेज और ससून

जनरल अस्पताल, पुणे

आयु परीक्षा के लिए प्रोफार्मा

24/8/2005

श्री नारायण चेतन चौधरी [2023] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यस्वदा केंद्रीय कारागार, पुणे द्वारा लाया गया

तारीख: 24/8/2005 , समय: 3: 45 अपराह्न, एम. एल. सी. संख्या 25802, तिथि: 23/8 2005

(अस्पष्ट 3 पंक्ति)

शारीरिक विकास: मध्यम

दाँत: ऊपरी 15 डब्ल्यूटी

68 किग्रा

निचला 15

एचटी 5 '9 "

दाढ़ी: मुंडन कराया।

प्यूबिक बाल: उपस्थित हैं।

आवाज़: सामान्य

जननांग: सामान्य

मेडिकोलेगल परीक्षा: एक्स रे प्लेट संख्या आर 180 (4) दिनांक: 23/8/05

(अस्पष्ट चिकित्सा विवरण)

निष्कर्ष: नैदानिक और रेडियोलॉजिकल परीक्षा से दिनांक 24/8/05 पर रोगी की आयु 'बाईस वर्ष से अधिक लेकिन चालीस वर्ष (40 वर्ष) से कम' जिसमें त्रुटि का अंतर भी शामिल है। की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए:

एसडी /

बीजी मोर

एसडी

डॉ. एम. एस.

वाबी

प्रो. & हेड/एससैका प्रो. / अस्स्टेट। लेका

फोरेंसिक चिकित्सा विभाग

बी. जे. मेडिकल कॉलेज, पुणे-411001

(पेपरबुक नारायण चेतनराम चौधरी बी. से शब्दशः उद्धृत किया गया।

महाराष्ट्र राज्य [अनिरुद्ध बोस, जे.]

5. यह 2006 के शुरुआती हिस्से में था, हमें श्री बसंत द्वारा अवगत कराया जाता है,

आवेदक का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि उनका मुद्दा कुछ मानवाधिकार समूहों द्वारा उठाया गया था। किशोरावस्था के मुद्दे पर आवेदक के मुद्दे का समर्थन करने वाले कुछ सार्वजनिक उत्साही व्यक्तियों ने 24 जनवरी 2006 को भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इस आधार पर मृत्युदंड के पुरस्कार को रद्द करने का अनुरोध किया था कि वह अपराध करने के समय किशोर था। उक्त संचार की एक प्रति, जिसका शीर्षक "दया याचिका" है, आवेदन के साथ ए-7 के रूप में संलग्न की गई है। इस याचिका का मूल पाठ नीचे दिया गया है: -

" राष्ट्रपति सचिवालय

सी

. ए. ॥ खंड

तिथि-

24/1/2006

डी. सं. 03-/

06 एम. पी.

राष्ट्रपति के समक्ष एक किशोर की ओर से दया याचिका

माननीय। महामान्या

माननीय। भारत के राष्ट्रपति,

राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

महामहिम, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति को

हम एक संगठन मानवाधिकार और कानून रक्षक हैं
(एचआरएलडी) मानवाधिकारों पर विभिन्न मुद्दों पर काम कर रहा है

उल्लंघन करते हैं। हम यरवदा केंद्रीय कारागार, पुणे में भी काम करते हैं।

और संकटग्रस्त कैदियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करें।

यह हमारे सामने मामले की चरम सीमा के कारण है कि हम लेते हैं
आपके माननीय के साथ पत्राचार करने की स्वतंत्रता। स्वयं आपको बनाने के लिए

पता है कि एक व्यक्ति का नाम निरनाराम चेतनराम है

चौधरी, जिनका जन्म 1/2/1982 पर हुआ था, जिन्हें सम्मानित किया गया है

यरवदा में एक हत्या के मामले में मौत की सजा

केंद्रीय कारागार, पुणे। इसलिए, यह आवेदक आसपास था
13 इस अपराध को करने के समय आयु के वर्ष। आपकी.

महामहिम, आपके कार्यालय को उनकी ओर से दया याचिका मिली है।

सह-अभियुक्त जितेंद्र नैनसिंह गहलोत 8/11 को डी. वाई. नंबर 7/27
2004. आपको वास्तव में सभी प्रासंगिक चीजें मिल रही हैं।

मामला सामग्री जो पहले आपके कार्यालय में भेजी गई हो।

सी आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस तथ्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करें कि निरनाराम चेतनराम नाबालिग था ताकि मौत हो जाए।

अपराध के समय चौधरी

दंड देना कानून की गलती है। यह भी होना चाहिए

अच्छी तरह से नोट किया गया है कि उच्च द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णय हैं न्यायालय और कई और मूल कानून

न्यायालय और सर्वोच्च

यह पुष्टि करने के लिए कि यदि कोई व्यक्ति उस समय किशोर था मजबूत आधार हो सकता है

अपराध करने के लिए, यह एक

मामले के किसी भी स्तर पर विचार। वह पहले ही खर्च कर चुका है।

चार दीवारों के अंदर 11 साल से अधिक समय से लटके हुए

जेल। हम गर्भपात को प्रकाश में लाना चाहते हैं

इस मामले में न्याय जहां एक 13 वर्षीय किशोर जो

एक अपराध अंदर एक वयस्क आदमी बन गया है

जेल का मतलब बड़े और कठोर अपराधियों के लिए था। तो हम चाहते हैं

आपसे एक किशोर के इस संवेदनशील मामले पर विचार करने का अनुरोध करने के लिए साथ टकराव में और अपने अगस्त कार्यालय से पूछें और

कानून के

मृत्युदंड की सजा को रद्द करने के लिए माननीय स्वयं

इस मामले में किशोर को पुरस्कृत किया गया।

वास्तव में आपका

एड. असीम सरोद एड. स्मिता लोखंडे जागृति संजय

जाधव

मोहत

मानवाधिकार कार्यकर्ता कानूनी सहायता वकील छात्र सामाजिक इंटरन कार्यकर्ता

घेराव: निरनाराम चेतनराम का स्थानांतरण प्रमाण पत्र

चौधरी और उनकी उम्र के प्रमाण के संबंध में अन्य कागजात।

(सभी सत्यापित प्रतियाँ) "

(पेपरबुक से शब्दशः उद्धृत)

6. वह पत्र, जैसा कि इस आवेदन में अनुरोध किया गया था, को भेज दिया गया था
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य सरकार की टिप्पणियों को उजागर किया
किशोरावस्था का एक भी दावा नहीं। बाद में हुआ था आदान-प्रदान
उनकी उम्र के सवाल पर अधिकारियों के बीच बातचीतखनन। अधीक्षक, यरवदा से उत्पन्न एक पत्र में
अल जेल, पुणे ने अपर सचिव, गृह विभाग को संबोधित किया,
राष्ट्र (जो वर्तमान आवेदन का अनुलग्नक ए-13 है),
अधिकारियों ने दर्ज किया कि चिकित्सा अधीक्षक, ससून अस्पताल,
आवेदक द्वारा सूचित किया गया था कि उसने सरकारी नारायण चेतनराम चौधरी बनाम में अध्ययन किया
था।

महाराष्ट्र राज्य [अनिरुद्ध बोस, जे.]

जलबसार में स्कूल और स्कूल में उनका नाम निरनाराम था। 19 जनवरी 2007 के इस पत्र में इसका उल्लेख किया गया था - उसका नाम निरनाराम है। हालाँकि, ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि आगे कोई आयु निर्धारण परीक्षण किया गया था। उक्त पत्र में लिखा है:

" उपरोक्त विषय के संदर्भ में, आदेश दिए गए थे

वर्तमान आयु के संबंध में एक चिकित्सा रिपोर्ट प्रस्तुत करें

दोषी कैदी सी. 1871 नारायण चेतनराम चौधरी।

तदनुसार, उक्त कैदी को माननीय मेडिकल अस्पताल भेजा गया।

अधीक्षक, ससून अस्पताल, पुणे और वे थे

पत्र एन. वी. 1/ए. वी. टी./64/2007 तिथि 8/1/2000 के माध्यम से अनुरोध किया गया
कैदी की उम्र के बारे में
मेडिकल रिपोर्ट देना।

उनके पत्र में एस. एस. आर./कैदी/26/06 तारीख 8/1/2007 के बारे में

कैदी की उम्र, माननीय। चिकित्सा अधीक्षक ने नोट किया कि ", कैदी से बात करने के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि उसका वास्तविक

उम्र का पता उसके स्कूल के रिकॉर्ड से लगाया जा सकता है। उसका नाम।

स्कूल में निरनाराम चेतनराम चौधरी थे और उन्होंने

उन्होंने कक्षा 3 तक जुलाबसर के सरकारी स्कूल में पढ़ाई की।

यह गाँव डूंगरगढ़ तालुका में है, जो पहले चुरू जिले में था।

अब बीकानेर जिला। यदि आप उससे प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं

स्कूल यह उपयोगी हो सकता है। " हमने एक फोटोकॉपी संलग्न की है

उनके वकील श्री असीम सरोदे द्वारा प्रस्तुत दया याचिका उसके साथ उसके स्कूल का प्रमाण पत्र भी संलग्न है। की फोटोकॉपी

कैदी द्वारा प्रस्तुत स्कूल प्रमाण पत्र किया जा रहा है

संलग्न।

जानकारी और आगे की कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किया गया।

(पेपरबुक से शब्दशः उद्धृत)

7. इसके बाद, इस न्यायालय में अनुच्छेद के तहत एक रिट याचिका दायर की गई थी

32 स्वयं का प्रतिनिधित्व करने वाले आवेदक द्वारा भारत के संविधान का

' नारायण @निरनाराम 'ने इस आधार पर उस पर लगाए गए सजा के आदेश को रद्द करने की मांग की कि वह किस तारीख को नाबालिग था।

अपराध का कमीशन। इस याचिका में, उपरोक्त प्रमाणपत्रों के अलावा, आवेदक ने 1989 में जारी राजस्थान सरकार के "परिवार कार्ड" पर भरोसा किया था, जिसमें निराना की आयु 12 वर्ष दर्ज की गई थी और साथ ही 15 अगस्त 2001 को जारी किए गए उपरोक्त स्थानांतरण प्रमाण पत्र में निरनाराम की जन्म तिथि 1 फरवरी 1982 दर्ज की गई थी। इन दोनों दस्तावेजों में चेतनराम का नाम निरनाराम के पिता के रूप में आता है।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डब्ल्यू. पी. के रूप में पंजीकृत रिट याचिका 2013 की (आपराधिक) संख्या 126 पर 12 अगस्त 2013 को इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया था।

उतरने का क्रम:

“ यू. पी. ओ. एन. सुनवाई वकील ने न्यायालय ने निम्नलिखित किया:

आदेश

ई अनुच्छेद के तहत इस रिट याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं

2 भारत के संविधान और उसी को खारिज कर दिया जाता है।

8. यह आवेदन 30 अक्टूबर 2018 को शुरू किया गया था। जब यह सुनवाई के लिए तैयार हुआ, तो एक समन्वय पीठ ने जनवरी 2019 को पारित एक आदेश द्वारा मामले को 2015 के अधिनियम की धारा 9 (2) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आवेदक की किशोरता पर निर्णय लेने के लिए प्रधान जिला और न्यायाधीश, पुणे को भेज दिया था। यह आदेश इस प्रकार है: 'यूपीओएन ने वकील को सुनकर न्यायालय ने निम्नलिखित किया:

आदेश

पक्षकारों की विद्वान सलाह सुनी। आवेदक-नारायण चेतनराम चौधरी ने आर. पी. में एक आवेदन (2016 का Crl.M.P.No.5242) दायर किया है। (सीआरएल।) नं. 1139 1140/2000 Crl.A.Nos.25-26/2000 में) की समीक्षा की मांग

आपराधिक मामले में इस न्यायालय का अंतिम निर्णय दिनांक 05.09.2000

2000 की अपील Nos.25-26, जिसके तहत उसकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया

भारतीय दंड संहिता की धारा 342, 397, 449 और 302 (इसके बाद 'आई. पी. सी.' के रूप में संदर्भित) और मौत की सजा

आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत उसे फिर से सम्मानित किया गया

समीक्षा याचिका (सी. आर. एल.) नं. 1139-1140 2000 का, जिसे इस न्यायालय द्वारा 24.11.2000 पर खारिज कर दिया गया था। आवेदक ने यह भी कहा

आर. पी. में एक आवेदन (2018 का Crl.M.P.No.157334) दाखिल किया।

(सीआरएल.) नं. 1139-1140 / 2000 Crl.A.Nos में। 25-26 / 2000) किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 9 (2) के तहत यह घोषणा करने की मांग की गई है कि वह उस समय किशोर था।

अपराध का कमीशन। आवेदक ने निश्चित किया है कि

अपराध का कमीशन। आई. डी. 1 पर, जब मामला सुनवाई के लिए इस न्यायालय के समक्ष आया, तो राज्य के वकील को नारायण चेतनराम चौधरी बनाम को निर्देशित किया गया।

महाराष्ट्र राज्य [अनिरुद्ध बोस, जे.]

आवेदक के किशोर होने के सवाल पर अतिरिक्त दस्तावेजों पर निर्देश लें। लेकिन आज, विद्वान

प्रत्यर्थी के लिए वकील-राज्य प्रस्तुत करता है कि उसे अभी तक उस संबंध में कोई निर्देश नहीं मिला है। यह तत्काल मामला राज्य के घोर सुस्त और लापरवाही भरे रवैये को दर्शाता है। मामले के लंबित होने को देखते हुए, हमें अवलोकन करने से रोक दिया गया है

आगे कुछ भी।

अधिनियम की धारा 9 (2) को ध्यान में रखते हुए, हमारे पास इस मामले को प्रधान जिले को भेजने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है

और सत्र न्यायाधीश, पुणे, आवेदक की किशोरता का निर्णय करने के लिए। तदनुसार, हम इस न्यायालय की रजिस्ट्री को आर. पी. में आवेदन (Crl.M.P.No.157334/2018) भेजने का निर्देश देते हैं। (सीआरएल।) नं. 1139-1140 / 2000 में Crl.A. संख्या. 25-26 / 2000) आवेदक द्वारा प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश, पुणे को आवेदक की किशोरता तय करने के लिए दस्तावेजों की ज़रॉक्स प्रति के साथ। यदि आवेदक को नोटिस दिया जाता है, तो उसे किशोरावस्था के अपने दावे के समर्थन में संबंधित न्यायालय के समक्ष सभी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।

अपराध करने का समय। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश, पुणे को निर्देश दिया जाता है कि वे इस न्यायालय को छह सप्ताह की अवधि के भीतर एक रिपोर्ट भेजें। हम आशा और विश्वास करते हैं

कि प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश, पुणे

निर्धारित समय के भीतर आवेदक की किशोरावस्था का निर्णय लें।

यहाँ ऊपर।

रिपोर्ट मिलने के तुरंत बाद मामले को सूचीबद्ध करें।

प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश, पुणे "

सकारात्मक रूप से रिपोर्ट को अस्वीकार करने और आवेदन को खारिज करने के लिए कहा गया है। जाँचकर्ता न्यायाधीश ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित बातों की जाँच की थी: रोगनिदान:

सी आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 1. राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, जलबसार शिक्षा द्वारा जारी एक स्थानांतरण प्रमाण पत्र दिनांक 15/08/2001

विभाग, राजस्थान, चुरू जिले के जलबसार निवासी, निरनाराम पुत्र चेतनराम के नाम पर, जन्म तिथि 01/02/1982 दिखा रहा है। (अनुलग्नक-'I-1' उनकी रिपोर्ट में)।

2. निरनाराम पुत्र चेतनराम की जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, दिनांक 30/01/2019, प्रधानाध्यापक, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, जलबसार द्वारा जारी किया गया,

श्रीदनगरगढ़ (बीकानेर)। (उसकी रिपोर्ट में अनुलग्नक 'I-2')।

3. प्रधानाध्यापक, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय,, जलबसार, श्रीदनगरगढ़, (बीकानेर), दिनांक 07/02/2019 द्वारा जारी स्कूल रजिस्टर की एक प्रति। (उसकी रिपोर्ट में अनुलग्नक 'I-3')। 4.

बोनाफाइड निवासी का प्रमाण पत्र दिनांक 10/08/2009, जारी किया गया

तहसीलदार, श्रीदनगरगढ़, बीकानेर द्वारा बीकानेर जिले के तहसील श्रीदनगरगढ़ के निवासी निरनाराम पुत्र चेतनराम के नाम पर। (अनुलग्नक-'I-4' उनकी रिपोर्ट में)।

5. बीकानेर जिले के जलबसार निवासी निरनाराम पुत्र चेतनराम के नाम पर तहसीलदार श्री डूंगरगढ़, बीकानेर द्वारा दिनांक 10/08/2009 पर जारी अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र। (अनुलग्नक-'I-5' उनकी रिपोर्ट में)।

6. राज्य द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23/03/2001 की एक प्रति

राजस्थान के तहसील को शामिल करने के संबंध में बीकानेर जिले में डूंगरगढ़ को 01/04/2001 से हटा दिया गया है। जिला चुरू से भी ऐसा ही है। (अनुलग्नक-'I-6' उनकी रिपोर्ट में)।

7. यह प्रमाणित करते हुए कि नारायण चौधरी वही व्यक्ति हैं जिनका दूसरा नाम निरनाराम पुत्र चेतनराम चौधरी है, श्रीडूंगरगढ़ के ग्राम पंचायत उदासर के सरपंच द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र। (अनुलग्नक-'I-7' उनकी रिपोर्ट में)।

8. वर्ष 1989 में चेतनराम पुत्र रत्नाराम के नाम से जारी राजस्थान सरकार का परिवार कार्ड No.21711 चेतनराम के पुत्र के रूप में 'निराना' की आयु 12 वर्ष दर्शाता है। इसके अलावा, अनादा, मुखराम, बीरबल को दिखाया जा रहा है

'निराना' के भाई। (अनुलग्नक-'एल-1' उनकी रिपोर्ट में)।

रायन चेतनराम चौधरी बनाम। महाराष्ट्र राज्य [अनिरुद्ध बोस, जे.]

9. राजकीय माध्यमिक विद्यालय द्वारा जारी एक टी. सी. प्रपत्र

उदासर, तहसील-श्रीदनगरगढ़, जिला-बीकानेर, दिनांक 19 /

09/2003 , अनादरम पुत्र चेतनराम सनातन के नाम पर। (अनुलग्नक-'एल-2' उनकी रिपोर्ट में)।

10. एक स्थानांतरण प्रमाणपत्र, दिनांकित 15/07/1994 के नाम पर

राजकिया जी. आर. मोहता द्वारा जारी मुखराम पुत्र चेतनराम

उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्रीदनगरगढ़, बीकानेर।

(अनुलग्नक-'एल-3' उनकी रिपोर्ट में)।

11. आयु के सत्यापन के लिए प्रोफार्मा की एक फोटोकॉपी

नारायण चेताराम के संबंध में परीक्षा, दिनांक 24/08/2005

चौधरी। (अनुलग्नक-'जे-1' अपनी रिपोर्ट में) "

(पेपरबुक से शब्दशः उद्धृत)

10. जाँचकर्ता न्यायाधीश का तर्क और निष्कर्ष

12 मार्च 2019 का टी निम्नलिखित शर्तों में था:

" 38) जहाँ तक जांच करने का निर्देश दिया गया है

न्यायालय प्रारम्भ में संबंधित प्रावधानों से संबंधित है -

किशोरता के संबंध में जांच के संबंध में कानून होना चाहिए

संदर्भ के लिए उल्लिखित। अधिनियम के तहत प्रावधान हैं -

जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है।

39) अधिनियम की धारा 2 (35) के अनुसार, किशोर का अर्थ है एक बच्चा।

18 वर्ष की आयु से कम। ऊपर उल्लिखित अधिकारी,
करते हुए

विशेष रूप से पूर्वव्यापीता का उल्लेख

किशोरावस्था के तथ्य पर वर्तमान कानून का अनुप्रयोग है

इसे लेकर कोई विवाद नहीं हो सकता। इसलिए,

अधिनियम की धारा 9 (2) के आधार पर एक प्रासंगिक प्रावधान है -
माननीय के समक्ष याचिका दायर की है

जिसे याचिकाकर्ता ने

भारत का सर्वोच्च न्यायालय यह घोषणा करने के लिए कि वह एक बच्चा था

अधिनियम के तहत। उक्त प्रावधान ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है। में

राजू-बनाम-हरियाणा राज्य का मामला [(2019) 14 एस. सी. सी. 401]

किशोर न्याय (देखभाल) के नियम 7 ए का संदर्भ है।

और बच्चों का संरक्षण) नियम 2007। उक्त नियम सौदा करता है

किशोरावस्था के दावे में न्यायालय द्वारा जांच करने के साथ।

उक्त नियमों के नियम 12 के उप-नियम 3 में कहा गया है कि

आयु निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। इसके बाद

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015

प्रक्रिया से संबंधित प्रासंगिक प्रावधान लागू हुआ इसके बाद आने वाला यू/सेकंड है। 9 अधिनियम
से। इसी तरह, [2023] 6 एस. सी. आर. की धारा 94।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह अधिनियम आयु के अनुमान और निर्धारण से संबंधित है। तैयार संदर्भ के लिए, इन सभी प्रावधानों को पुनः प्रस्तुत किया गया है

ऊपर। 40) सुरेंद्र कुमार-बनाम-राज्य के अधिकारी

राजस्थान [(2008) एस. सी. सी. ऑनलाइन राज 138] "और" शाह नवाज-बनाम-उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य [(2011) 13 एस. सी. सी. 751] "स्कूल रिकॉर्ड के संदर्भ में प्रासंगिक हैं। इसी तरह, "सुरेंद्र कुमार (ऊपर)" का अधिकार मतदाता सूची में प्रवेश के संबंध में उपयोगी है। "दर्गाराम उर्फ गुंगा-बनाम-राजस्थान राज्य [(2015) 2 एस. सी. सी. 775]" का अधिकार अस्थिरकरण परीक्षण के संबंध में उपयोगी है। इन सभी मामलों को होना चाहिए "राजू (उपर्युक्त)" के मामले और ऊपर उल्लिखित कानून के प्रावधानों के संदर्भ में विचार किया गया।

41) उपरोक्त धारा 94 के प्रावधान के अनुसार, इस बारे में संदेह के मामले में कि कोई व्यक्ति बच्चा है या नहीं, उम्र की प्रक्रिया निर्धारण किया जाएगा और साक्ष्य होगा

संबंधित स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र या मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं।

निगम, नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत भी प्राप्त की जा सकती है और इसके अभाव में, आयु का निर्धारण अस्थिरकरण परीक्षण द्वारा किया जा सकता है। 42) इसलिए, यदि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 के नियम 7 ए को इसके नियम 12 और अधिनियम की वर्तमान धारा 9 और धारा 94 के साथ पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट है कि स्कूल प्रमाण पत्र से जन्म तिथि या

मैट्रिक प्रमाण पत्र या निगम का प्रमाण पत्र आदि।

प्रासंगिक विचार है। इस प्रकार, स्कूल प्रमाणपत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यहां तक कि "राजू (उपरोक्त)" के मामले में भी भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि स्कूल प्रमाण पत्र नाम के साथ-साथ जन्म तिथि के लिए भी प्रासंगिक होगा।

43) कानून के उपरोक्त प्रावधानों और अभिलेख पर रखे गए अधिकारियों को ध्यान में रखते हुए, मैं दस्तावेजों की जांच करने के लिए आगे बढ़ता हूं कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है वे वास्तविक और प्रामाणिक हैं और क्या किशोरावस्था तय करने के लिए उन पर भरोसा किया जा सकता है। याचिकाकर्ता की ओर से जाने-माने डी. जी. पी. और जाने-माने अधिवक्ता द्वारा की गई दलीलों पर एक साथ विचार किया जाएगा।

रायन चेतनराम चौधरी बनाम। महाराष्ट्र राज्य [अनिरुद्ध बोस, जे.]

44) पुलिस अधिकारी ने राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, जलबसार का दौरा किया था। उन्होंने प्रभारी प्रधान शिक्षक नम्रता प्रभुसिंह का बयान दर्ज किया है।

क्रम सं. में दस्तावेज़ का संदर्भ। 1 (अनुलग्नक-'I-1')। उक्त दस्तावेज़ "निरनाराम पुत्र चेतनराम" के नाम पर है। उसने कहा है कि उक्त दस्तावेज़ उसके स्कूल द्वारा स्कूल में रखे गए रजिस्टर के आधार पर जारी किया गया था। उन्होंने यह भी प्रमाणित किया कि प्रवेश संख्या। 568 रखे गए रजिस्टर के अनुसार सही है। रजिस्टर की प्रति, जो क्रम संख्या में दस्तावेज़ है। 3 (अनुलग्नक-'I-3') भी पाया गया।

पुलिस अधिकारी द्वारा रजिस्टर की सही प्रति होना

विद्यालय द्वारा रखा गया। ऐसे रजिस्टर में निरनाराम पुत्र चेतनराम का नाम देखा जा सकता है। इस तरह के रजिस्टर के अनुसार, "निरनाराम" की जन्म तिथि 01/02/1982 है। दस्तावेज़ के अनुसार भी

नहीं। 1 , "निरनाराम" की जन्म तिथि 01/02/1982 है। के साथ क्रम संख्या में दस्तावेज़ को ध्यान में रखते हुए। 2 (अनुलग्नक-'I-2'), पुलिस अधिकारी ने पाया कि यह उस स्कूल द्वारा जारी किया गया था जिसके

उस पर मुहर लगाएँ। केवल इसलिए कि इसकी दूसरी प्रति स्कूल में नहीं मिली थी या कि संबंधित रजिस्टर में नामों का कुछ अधिलेखन था, हालांकि "निरनाराम" के नाम का नहीं, ये हैं

दस्तावेज़ों को खारिज नहीं किया जा सकता है। क्रम संख्या में दस्तावेज़। 1 3 को स्कूल के आधार पर जारी किया गया प्रतीत होता है रिकॉर्ड करें "। निरनाराम को 1-04-1986 को स्कूल में भर्ती कराया गया था। इस प्रकार, हस्तांतरण प्रमाण पत्र दिनांकित 15/08/2001 अर्थात् क्रम संख्या पर दस्तावेज़। 1 यह पहला प्रमाणपत्र है।

45) पुलिस अधिकारी ने राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक को "मुखराम" द्वारा दिए गए पत्र की प्रतियां एकत्र कीं।

अपने भाई का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विद्यालय, जलबसार। ऐसी प्रतियां रिपोर्ट एक्सएच के साथ प्रस्तुत की जाती हैं। 16. इसी तरह, पुलिस अधिकारी को संबोधित एक नया प्रमाण पत्र भी दिया गया था

हेड मिस्ट्रेस द्वारा दिनांकित 23/02/2019 द्वारा दिया जाता है और इसे एकत्र किया जाता है और पुलिस अधिकारी द्वारा Exh.16 के साथ उसकी रिपोर्ट के साथ दाखिल किया जाता है। इसलिए, क्रम संख्या में दस्तावेज़। 1 3 तक, एक वास्तविक स्रोत है और वे प्रामाणिक दस्तावेज़ हैं। यह एक

तथ्य यह है कि इन दस्तावेज़ों में "नारायण" नाम का खुलासा नहीं किया गया है। इस पहलू पर बाद में विचार किया जाएगा, क्योंकि पुलिस अधिकारी को भेजने का उद्देश्य केवल दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता का सत्यापन करना था। उनसे अपनी राय व्यक्त करने की अपेक्षा नहीं की जाती थी। यह पर्याप्त है कि, [2023] 6 एस. सी. आर. के दस्तावेज़।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

46) क्रम संख्या में दस्तावेज़। 4 और 5 (अनुलग्नक-I-4 और I-5) तहसीलदार, श्रीदनगरगढ़ द्वारा जारी प्रामाणिक निवास और ओ. बी. सी. जाति प्रमाण पत्र के दस्तावेज़ हैं। क्रम सं. पर दस्तावेज़। 6 (अनुलग्नक-'I-6') विवादित नहीं है और यह दर्शाता है कि, 01/04/2001 से प्रभावी है। तहसील-श्रीदनगरगढ़, जो पहले चूरु जिले में था, को वहां से हटा दिया गया और बीकानेर जिले में शामिल कर लिया गया। इसलिए, हालांकि दिनांकित 15/08/2001 (दस्तावेज़ संख्या 1) प्रमाण पत्र में जिला चूरु का उल्लेख है, लेकिन दिनांकित 23/03/2001 अधिसूचना के आधार पर, श्रीदनगरगढ़ के गाँव जलबसर को बीकानेर जिले में शामिल किया गया है। प्रमाणपत्रों में

दस्तावेज़ क्रम संख्या। 4 और 5 में गाँव जलबसर और तहसील श्रीदनगरगढ़ के लिए बीकानेर जिले का उल्लेख है। ये

प्रमाणपत्र दिनांकित 10/08/2009 हैं। इसलिए, यह स्पष्ट है कि उस पर जिले बीकानेर का नाम उल्लिखित किया गया है। 47) क्रम संख्या में दस्तावेज़। 4 और 5 यानी तहसीलदार द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों को प्रामाणिक और वास्तविक कहा जा सकता है। पुलिस अधिकारी तहसीलदार के कार्यालय गए थे और

रजिस्टर में दोनों प्रमाणपत्रों की प्रविष्टियों का सत्यापन किया गया

तहसीलदार द्वारा अनुरक्षित। पुलिस अधिकारी द्वारा भवानीसिंह पुत्र प्रभुदन नामक तहसीलदार का बयान भी दर्ज किया गया। उनका बयान यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि दोनों प्रमाण पत्र क्रम संख्या में हैं। 4 और 5 तहसीलदार, श्रीदनगरगढ़, जिला बीकानेर के कार्यालय द्वारा जारी किए गए थे। की प्रतियाँ पुलिस अधिकारी द्वारा संबंधित रजिस्टर एकत्र किए गए हैं और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। रजिस्ट्रों में की गई प्रविष्टि की क्रम संख्याएं क्रम संख्या पर दस्तावेज़ों में प्रमाण पत्रों पर क्रम संख्या से मेल खाती हैं। 4 और 5. इसलिए, यह मानने का कोई कारण नहीं है कि रजिस्टर को ठीक से नहीं रखा गया था। पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर की प्रतियां तहसीलदार द्वारा प्रमाणित की गई हैं।

श्रीदनगरगढ़, जिला बीकानेर। इस प्रकार, क्रम संख्या में दस्तावेज़ों के प्रमाण पत्र। 4 और कहा जा सकता है कि 5 तहसीलदार श्रीदनगरगढ़, जिला बीकानेर द्वारा जारी किए गए थे। इस प्रकार, स्रोत वास्तविक है जो उन दस्तावेज़ों को रायन चेतनराम चौधरी बनाम बनाता है।

महाराष्ट्र राज्य [अनिरुद्ध बोस, जे.]

वास्तविक और प्रामाणिक। मान लीजिए, उस पर नाम है

"निरनाराम पुत्र चेतनराम "और" नारायण "नहीं।

48) क्रम संख्या में दस्तावेज़ के संबंध में। 9 (अनुलग्नक-'एल 2'), यह "अंदाराम पुत्र चेतनराम" के नाम का एक प्रमाण पत्र है। पुलिस अधिकारी ने राजकिया का दौरा किया था

"अंदाराम" के टी. सी. रूप की जांच करने के लिए माध्यमिक विद्यालय उदासरा। उन्होंने उक्त विद्यालय की एक व्याख्याता पूनम जयराम सिंह का भी बयान दर्ज किया। वह स्कूल की प्रभारी प्रधानाध्यापिका थीं। उनके अनुसार, प्रमाण पत्र टी. सी. प्रपत्र अर्थात क्रम सं. पर दस्तावेज़। 9 उसके स्कूल द्वारा जारी किया गया था। इस प्रकार, केवल इस कारण से कि इसकी प्रति नहीं थी, उक्त टी. सी. प्रपत्र को खारिज नहीं किया जा सकता है। टी. सी. प्रपत्र स्कूल रजिस्टर के आधार पर दिया गया था। इस तरह के स्कूल रजिस्टर की प्रति एकत्र की गई थी और इसे पुलिस अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया गया है। धारावाहिक No.1269 में, "अंदाराम पुत्र चेतनराम" के नाम की प्रविष्टि है। इस प्रकार, क्रम संख्या में दस्तावेज़ का प्रमाण पत्र। 9 यह वास्तविक और प्रामाणिक भी है।

49) क्रम संख्या में दस्तावेज़ के संबंध में। 10 (अनुलग्नक-'एल 3'), याचिकाकर्ता के वकील द्वारा कोई दावा नहीं किया गया है और उन्होंने व्यक्त किया कि वह इस बात पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं होंगे कि उसके अनुरूप मूल रिकॉर्ड किसी अन्य छात्र का कैसे पाया गया। इस प्रकार, क्रम संख्या में दस्तावेज़। 10 उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। क्रम सं. पर दस्तावेज़। 8

(अनुलग्नक-'एल-1') परिवार कार्ड है। ऐसे दस्तावेज़ के संबंध में, पुलिस अधिकारी ने बयान दर्ज किया

ग्रामसेवक, जिन्होंने कहा है कि, वर्ष 1989 का रिकॉर्ड

पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं था। पुलिस अधिकारी द्वारा की गई जांच को गलत तरीके से निर्देशित किया गया था क्योंकि उन्हें पंचायत समिति श्रीदनगरगढ़ के विकास अधिकारी से परिवार कार्ड यानी क्रम संख्या में दस्तावेज़ के बारे में पूछताछ करने की आवश्यकता थी। 8 . चूंकि ऐसी कोई जांच नहीं की गई थी, इसलिए यह कहा जा सकता है कि राज्य ने परिवार कार्ड की प्रामाणिकता की गंभीरता से खोज नहीं की। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, क्रम संख्या में दस्तावेज़। 9 यह वास्तविक है और यह "अंदाराम" के नाम पर है। उनके पिता का नाम "चेतनराम" है। क्रम संख्या में दस्तावेज़। 1 5 तक पिता का नाम दिखाएँ

" चेतनराम "। स्कूल के रिकॉर्ड भी इसी तरह का संकेत देते हैं।

सी आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसके अलावा, "निरनाराम" और "अंदाराम" के पिता के नाम के अलावा गाँव और जिले का नाम एक ही है। इस प्रकार, यह मानने का आधार है कि "चेतनराम" "निरनाराम" और "अंदाराम" के पिता हैं। परिवार कार्ड अर्थात् क्रम सं. पर दस्तावेज़ 8, "चेतनराम" के नाम पर है। गाँव का नाम जलबसर है और नाम "अनादा" और

" उसमें निराना को "चेतनराम" के पुत्रों के रूप में देखा जा सकता है। इस प्रकार, परिवार कार्ड अर्थात् क्रम संख्या पर दस्तावेज़ 8

बहुत अच्छी तरह से भरोसा किया जा सकता है। 50) क्रम सं. पर दस्तावेज़ 7 (अनुलग्नक-'I-7') को पुलिस अधिकारी द्वारा जाली दस्तावेज़ बताया गया है। यह गौरादेवी द्वारा गाँव उदारसर के पंच के रूप में जारी किया गया है। उन्होंने दस्तावेज़ में क्रम संख्या में प्रमाणित किया था। 7 कि,

" नारायण चौधरी "और" निरनाराम "एक ही व्यक्ति का नाम है। उनका बयान, उनके बेटे जेथाराम एस/ओ का बयान

पुलिस अधिकारी ने तोदाराम और उदाराम नाम के एक ग्रामीण को दर्ज किया। उन सभी ने क्रम संख्या में दस्तावेज़ को अस्वीकार कर दिया। 7 . हालांकि, पुलिस अधिकारी ने एक और दस्तावेज़ एकत्र किया है, जिसमें उसके समर्थन में ग्रामसेवक केसराराम का बयान दर्ज किया गया है और उस पर सरपंच गौरादेवी के हस्ताक्षर हैं। हालाँकि, पुलिस अधिकारी द्वारा एकत्र किए गए दस्तावेज़ पर सरपंच के हस्ताक्षर

केसराराम का बयान और क्रम संख्या में दस्तावेज़ पर उनके हस्ताक्षर। 7 समान प्रतीत होता है। इस प्रकार, उन परिस्थितियों में जब गौरादेवी ने स्वीकार किया कि वह एक सरपंच थीं, जो क्रम संख्या में दस्तावेज़ था। 7 सरपंच के हस्ताक्षर के बारे में संदेह नहीं किया जा सकता है। गौरादेवी न देख पाती थीं और न ही पढ़ पाती थीं। जब पुलिस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर की तुलना के लिए एक दस्तावेज़ एकत्र किया गया है, तो जेथाराम और उदाराम के बयान ज्यादा प्रासंगिक नहीं होंगे। उस पर सरपंच के हस्ताक्षर और 'पर दस्तावेज़

सीरियल नं. 7 समान प्रतीत होता है। इसलिए, यहां तक कि क्रम संख्या में दस्तावेज़ भी। 7 विचार किया जा सकता है।

51) अधिनियम की धारा 94 के अनुसार, केवल तभी जब विद्यालय प्रमाण पत्र या पंचायत और निगम का प्रमाण पत्र हो।

आदि नहीं पाए जाते हैं, ऑसिफिकेशन परीक्षण का सहारा लिया जा सकता है। चूंकि, इस मामले में प्रामाणिक स्कूल प्रमाण पत्र रिकॉर्ड में हैं, इसलिए इस समय क्रम संख्या में दस्तावेज़ पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 11 (संलग्नक-'जे-1')।

रेयान चेतनराम

चौधरी वी. राज्य

महाराष्ट्र [अनिरुद्ध बोस, जे.]

52) ऊपर वर्णित दस्तावेजों को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है

ऐसा प्रतीत होता है कि "चेतनराम" उनके पिता हैं। वे निवासी हैं।
जिसकी चर्चा पूर्वगामी में की गई है

जलबसार का। स्कूल रिकॉर्ड,

पैराग्राफ, अनादरम एस/ओ की जन्म तिथि को इंगित करते हैं

चेतनराम "04/04/1980 होना चाहिए, जबकि जन्म तिथि

" निरनाराम "01/02/1982 प्रतीत होता है। अतः इनमें से

स्कूल के दस्तावेजों में यह कहा जा सकता है कि "अनादरम" उससे बड़ा है।

" निरनाराम "। परिवार कार्ड में अर्थात क्रमवार दस्तावेज में

नहीं। 8 , यही स्थिति है क्योंकि "अनादरम" दिखाई दे रहा है
पिता के नाम के बाद से

"निरनाराम" से बड़ा होना। यहाँ,

उसी तरह, में की गई टिप्पणियों से मदद ली जा सकती है
द्वारा "राजू (ऊपर)" का मामला।

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय

यदि प्रमाणपत्रों को दस्तावेज के संदर्भ में पढ़ा जाता है
कि "निरनाराम" और "नारायण"

सीरियल नं. 7 , यह कहा जा सकता है

एक ही व्यक्ति है। रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है

दिखाएँ कि "चेतनराम" का एक और बेटा था जिसका नाम था

" नारायण "। यहां तक कि प्रमाण पत्र (क्रम संख्या में दस्तावेज)। 7), है

इन दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि "निरनाराम" भाई है।
भाई-बहन हैं। कुछ भी नहीं है

"अनादरम" का। इसलिए दोनों

दिखाएँ कि, "निरनाराम चेतनराम" नाम का कोई अन्य व्यक्ति

वह गाँव जलबसार में पाया गया था। इसलिए, दस्तावेजों से

अभिलेख पर, क्रम संख्या में दस्तावेज। 7 विश्वास भी किया जा सकता है।

हालांकि, किसी भी दस्तावेज में "नारायण" नाम का उल्लेख नहीं है।

"निरनाराम" नाम को दूसरा नाम कहा जाना चाहिए।

" नारायण "।

53) हालांकि, विशेष रूप से निर्णय को आधार बनाने के लिए नहीं, बल्कि

सामान्य अर्थ में सामान्य अवलोकन, यह कहा जा सकता है कि,

राजस्थान के लोग उच्चारण करने के आदी हो सकते हैं

" निरनाराम "आसानी से, लेकिन राज्य के लोग

महाराष्ट्र, विशेष रूप से पुणे में, मुश्किल हो सकती है

"निरनाराम" का उच्चारण करें। इस कारण से, उच्चारण में गलती से "निरनाराम" कहने की संभावना है।

" नारायण "पुणे में।

सी आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

54) अगर 'निरनाराम' 'नारायण' नहीं है और 'नारायण' कोई और व्यक्ति है, तो राज्य को यह स्पष्ट करना चाहिए था

नारायण के स्कूल रिकॉर्ड के दस्तावेजी साक्ष्य में उन्हें अलग व्यक्ति दिखाया गया है। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस प्रकार, सत्र मामले के पुलिस रिकॉर्ड में बिना कुछ पूछे "नारायण" नाम दिखाया गया होगा।

स्कूल रिकॉर्ड में उनके नाम के रूप में पहचान दस्तावेज।

यह दिखाने के लिए राज्य द्वारा एक भी दस्तावेज दायर नहीं किया गया है कि "नारायण के" पिता का नाम "चेतनराम" नहीं है, बल्कि यह अलग है। 55) विद्यालय के दस्तावेजों और तहसीलदार द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों को देखते हुए, याचिकाकर्ता की जन्म तिथि

01/02/1982 प्रतीत होता है। इस तरह, उनकी उम्र 24/08/1994 पर

यह लगभग 12 साल और 6 महीने का होगा। यदि परिवार कार्ड, जो वर्ष 1989 में जारी किया गया था, देखा जाए तो उसमें उल्लिखित आयु 12 वर्ष है। यदि यह वर्ष 1989 के लिए उल्लिखित आयु है, तो वर्ष 1994 में, विशेष रूप से 24/08/1994 पर, याचिकाकर्ता की आयु 16 वर्ष और 8 महीने होगी। इस प्रकार, यह अभी भी 18 वर्ष से कम है।

56) जब स्कूल रिकॉर्ड उपलब्ध हो, तो ऑसिफिकेशन टेस्ट पर विचार नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, भले ही दस्तावेज क्रम संख्या में हो। 11 ध्यान में रखा जाए तो उल्लिखित सीमा 22 वर्ष है। वर्ष 2005 में 40 वर्ष तक। इस प्रकार, वर्ष 1994 के लिए यह सीमा 11 वर्ष से 29 वर्ष तक आ जाएगी। यह प्रमाणपत्रों का भी समर्थन करता है, विशेष रूप से क्रमिक दस्तावेजों का।

नं. 1 5, 8 और 9 तक। उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, यह बहुत स्पष्ट है कि, घटना की तारीख यानी 24 अगस्त को।

1994 याचिकाकर्ता की आयु लगभग 12 वर्ष और 6 महीने थी। इस प्रकार, वह अधिनियम की धारा 2 (35) के अर्थ में एक बच्चा या किशोर था।

निष्कर्ष:

57) 24/08/1994 पर, निरनाराम चेतनराम की आयु 12 वर्ष और 6 महीने या लगभग उतनी ही थी। नारायण चेतनराम चौधरी वही व्यक्ति हैं, जिनका दूसरा नाम नारायण चेतनराम चौधरी बनाम है।

महाराष्ट्र राज्य [अनिरुद्ध बोस, जे.]

निरनराम चेतनराम चौधरी। इसलिए मेरा मानना है कि

याचिकाकर्ता अपराध करने की तारीख को नाबालिग था।

इसलिए, रिपोर्ट "।

(पेपरबुक से शब्दशः उद्धृत)

11. श्री पाटिल का पहला निवेदन है कि किशोरावस्था का सवाल है।

इस आवेदन द्वारा फिर से नहीं खोला जा सकता है क्योंकि आवेदक ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 (2013 की रिट याचिका (आपराधिक) No.126) के तहत इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की थी और इस रिट याचिका को इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया है कि आवेदक किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित रिकॉर्ड पर भरोसा कर रहा है क्योंकि पहले किसी भी समय उसने यह खुलासा नहीं किया था कि उसका असली नाम निरनाराम था। यहाँ तक कि आगे भी

इस आधार पर कि आवेदक का वास्तविक नाम निरनाराम है, श्री पाटिल चाहते हैं कि हम दस्तावेजी साक्ष्यों के पूरे सेट को यह आरोप लगाते हुए खारिज कर दें कि ये दस्तावेज, विशेष रूप से स्कूल के रिकॉर्ड, मनगढ़ंत हैं। उन्होंने आवेदक के परिवार के सदस्यों और उनकी उम्र के संबंध में दस्तावेजों में कुछ विसंगतियों पर प्रकाश डाला है। विशेष रूप से, उन्होंने प्रस्तुत किया है कि आवेदक के परिवार के सदस्यों ने सरपंच का एक जाली प्रमाण पत्र बनाया था, जिसे रिपोर्ट में अनुलग्नक I-7 के रूप में चिह्नित किया गया था। उन्होंने पंच गौरादेवी के बयान की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है, जैसा कि जांच रिपोर्ट में दर्ज है। जैसा कि रिपोर्ट में खुलासा किया गया है, उसने कहा था कि उसने कभी भी वह प्रमाण पत्र जारी नहीं किया था। उन्होंने भी

हमें अंदराम के हस्तांतरण प्रमाण पत्र (कुछ दस्तावेजों में अनादराम और आनंदराम के रूप में संदर्भित) के माध्यम से लिया गया, जिसे रिपोर्ट में एल-2 के रूप में चिह्नित किया गया था और मुखराम का, जिसे उसमें एल-3 के रूप में चिह्नित किया गया था। जैसा कि प्रतीत होता है।

जाँच रिपोर्ट से, ये दोनों व्यक्ति आवेदक के भाई हैं। उन्होंने रिपोर्ट के उस हिस्से का उल्लेख किया है, जिसमें जांच न्यायाधीश ने दर्ज किया है कि स्कूल की प्राचार्य श्रीमती. नम्रता ने कहा था कि प्रवेश संख्या 1317 (जो मुखराम के स्थानांतरण प्रमाण पत्र में दर्ज थी) में स्कूल के रिकॉर्ड में मुखराम का नाम नहीं था, लेकिन प्रवेश संख्या 1317 एक बाबूलाल के नाम पर था।

श्रीचंदनमल भदानी, जिनकी जन्म तिथि 6 जून 1966 थी। स्कूल के प्रधानाचार्य ने आगे कहा कि उक्त स्थानांतरण प्रमाण पत्र था इस पर स्कूल के तत्कालीन प्रिंसिपल ने हस्ताक्षर नहीं किए थे और यह कभी भी स्कूल द्वारा जारी नहीं किया गया था। श्री पाटिल द्वारा यह भी कहा गया है कि आवेदक के परिवार के सदस्यों ने फोटो चिपकाकर निरनाराम का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया था और 10 अगस्त 2009 को तहसीलदार अधिकारी श्री डूंगरगढ़ द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया था जब आवेदक जेल में था।

23] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12. श्री पाटिल ने जांच के तरीके पर भी सवाल उठाया है। उनका मुख्य निवेदन है कि जांच की अभिव्यक्ति के रूप में 2015 के अधिनियम की धारा 9 (2) में नियोजित व्यक्ति को दंड संहिता की धारा 2 (जी) के तहत दिए गए समान अर्थ का प्रयोग करना चाहिए।

प्रक्रिया, 1973 ("1973 संहिता")। इस संबंध में उन्होंने राम विजय सिंह-बनाम-उत्तर प्रदेश राज्य [2021 एस. सी. सी.] के मामलों का उल्लेख किया है। ऑनलाइन एस. सी. 142] और अश्विनी कुमार सक्सेना-बनाम मध्य प्रदेश राज्य [(2012) 9 एस. सी. सी. 750]। राम विजय सिंह (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने पाया कि प्रक्रिया में निर्धारित किया गया है

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 ("2000 अधिनियम") के तहत बनाए गए नियमों का नियम 12 2015 के अधिनियम की धारा 94 के प्रावधानों से भौतिक रूप से अलग नहीं है। वह चाहते हैं कि हम अश्विनी कुमार सक्सेना (उपरोक्त) के मामले में इस अदालत के दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा किए गए निष्कर्ष में अंतर करें, जिसमें अबुजर हुसैन उर्फ गुलाम हुसैन-बनाम-पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में निर्णय का उल्लेख किया गया है।

[(2012) 10 एस. सी. सी. 489] उन्होंने प्रस्तुत किया है कि 2015 के अधिनियम की धारा 9 (2) के अधिदेश का पालन करने के लिए जांच न्यायाधीश को निर्धारण के लिए शपथ पर भौतिक गवाहों के साक्ष्य दर्ज करने चाहिए थे।

उसकी उम्र अधिक थी लेकिन उसने जल्दबाजी में जाँच पूरी कर ली। 13. श्री चिताली की प्रस्तुतियाँ एक ही पंक्ति में हैं। पवन कुमार गुप्ता बनाम राज्य के इस मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा करते हुए

(एन. सी. टी. दिल्ली) [(2020) 2 एस. सी. सी. 803], उन्होंने तर्क दिया है कि एक बार नाबालिग होने के लिए आवेदक की याचिका खारिज हो जाने के बाद, उनके लिए उसी दावे को फिर से शुरू करने के लिए खुला नहीं था। जहां तक आवेदक के नाम का संबंध है, उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया है कि सरपंच का प्रमाण पत्र जाली था और दावे को साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत नहीं था। मतदाता सूची में जिस प्रविष्टि में निरनाराम चेतनराम चौधरी का नाम आता है, उसके संबंध में उन्होंने बताया है कि 1993 की उक्त सूची से पता चलता है कि

आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। उनका दूसरा निवेदन यह है कि किशोरावस्था की याचिका को कार्यवाही की स्थापना के निकटता में उठाया जाना चाहिए। इस बिंदु पर उनके द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे मुरारी ठाकुर और एक अन्य-बनाम-बिहार राज्य के मामले हैं [(2009) 16 एस. सी. सी.

256] , पवन-बनाम-उत्तरांचल राज्य [(2009) 15 एससीसी 259], मोहम्मद अनवर-बनाम-राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) [(2020) 7 एस. सी. सी. 391] और सूरजदेव महतो और एक अन्य-बनाम-राज्य बिहार [(2022) 11 एस. सी. सी. 800]। अपराध की क्रूरता और संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए न्यायिक पदानुक्रम के सभी स्तरों पर साबित होने के बाद, उसने अबूजर हुसैन (उपरोक्त) के मामले से निम्नलिखित अंश की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है:

नारायण चेतनराम चौधरी बनाम। महाराष्ट्र राज्य [अनिरुद्ध बोस, जे.]

" 39.6 किशोरता की विश्वसनीयता में कमी या किशोरता के तुच्छ दावे या किशोरता के स्पष्ट रूप से बेतुके या स्वाभाविक रूप से असंभव दावे के दावे को जब भी उठाया जाए तो अदालत द्वारा खारिज कर दिया जाना चाहिए।

14. जैसा कि उक्त रिपोर्ट में निहित तर्क से स्पष्ट होगा, जांच न्यायाधीश द्वारा स्कूल पर पर्याप्त जोर दिया गया था

प्रवेश रजिस्टर, जिसके आधार पर जन्म तिथि का "प्रमाण पत्र" जारी किया गया था। इस दस्तावेज़ का उल्लेख करते हुए, जिसका मूल हम देख चुके हैं, यह प्रस्तुत किया गया है कि उसमें प्रविष्टियाँ सही क्रम में नहीं थीं। उदाहरण देने के लिए, श्री पाटिल ने प्रस्तुत किया है कि प्रविष्टि संख्या 550 16 अगस्त 1984 को कक्षा 4 में प्रवेश करने वाले पदधारी से संबंधित है, जबकि प्रविष्टि संख्या 551 4 सितंबर 1985 को कक्षा 1 में पदधारी के प्रवेश को दर्शाती है। चार अन्य प्रविष्टियों, 552, 553, 554 और 565 में अपने पदधारियों के प्रवेश की तारीखों का क्रम दिखाया गया है।

असममित क्रम। वास्तव में, उनका निवेदन रहा है कि यह प्रविष्टि रजिस्टर निर्मित किया गया था और पृष्ठों में हेरफेर किया गया था। उसके आगे

इस आधार पर निवेदन यह है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 ("1872 अधिनियम") की धारा 35 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, 1 फरवरी 1982 के रूप में दर्ज निरनाराम की जन्म तिथि को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इस आधार पर उन्होंने रविंदर सिंह गोरखी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(2006) 5 एस. सी. सी. 584] और रामदेव चौहान उर्फ राज नाथ बनाम असम राज्य [(2001) 5 एस. सी. सी. 714] के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया है। प्रवेश रजिस्टर में प्रविष्टि के संभावित मूल्य पर, उन्होंने विराद मल सिंघवी के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया है।

-बनाम-आनंद पुरोहित [(1988) पूरक एस. सी. सी. 604]। इस बिंदु पर, उनका निवेदन है कि किसी व्यक्ति की उम्र के संबंध में प्रविष्टि का उस उम्र को साबित करने के लिए बहुत अधिक प्रमाणिक मूल्य नहीं है, क्योंकि ऐसी सामग्री नहीं है जिस पर उसकी उम्र स्कूल रजिस्टर में दर्ज की गई थी। उन्होंने हमें 1 जनवरी 1989 के "परिवार कार्ड" के माध्यम से भी बताया है, जिसमें अंडाराम, निरनाराम और मुखराम के जन्म के वर्ष 1976, 1977 और 1979 होने चाहिए। विद्यालय के अभिलेखों के अनुसार, ये वर्ष 1980, 1982 और 1983 होने चाहिए थे। 1 जनवरी 1993 की मतदाता सूची में निरनाराम की आयु 18 वर्ष थी। जिन मामलों में इस न्यायालय द्वारा किशोरता की याचिका स्वीकार की गई थी, श्री पाटिल की तर्क यह है कि सीमा रेखा मामलों में आयु निर्धारण 16 से 18 वर्ष के बीच किया गया था। उन्होंने इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला है कि जिस समय याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था, किशोर न्याय अधिनियम, 1986 ("1986 अधिनियम") लागू था।

23] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

15. हम सबसे पहले निरनाराम की वास्तविक पहचान के मुद्दे की जांच करेंगे। क्या वह वही व्यक्ति है जिसे दोषी ठहराया गया है और बाद में नारायण को मौत की सजा सुनाई गई? यहां तक कि पुनर्विचार याचिका में भी आवेदक ने खुद को नारायण चेतनराम चौधरी बताया। पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने की तिथि 31 अक्टूबर 2000 है। हमारे सामने मौजूद सामग्रियों से हम पाते हैं कि निरनाराम चेतनराम चौधरी के रूप में उनकी पहचान जनवरी 2006 के शुरुआती हिस्से में सामने आई थी, जैसा कि आवेदन के अनुलग्नक ए-7 से दिखाई देगा। इस संचार को "राष्ट्रपति के लिए एक किशोर की ओर से दया याचिका" के रूप में शीर्षक दिया गया है। इस दया याचिका में आवेदक को निरनाराम के रूप में संदर्भित किया गया है। कुछ सार्वजनिक भावनाएँ

एक वकील सहित व्यक्ति इस "दया याचिका" के हस्ताक्षरकर्ता हैं। इसके बाद गृह विभाग को संबोधित एक पत्र आता है अधीक्षक, यरवदा, केंद्रीय कारागार दिनांक 19 जनवरी 2007 द्वारा महाराष्ट्र सरकार। हमने इस निर्णय के पहले भाग में इस पत्र के पाठ को पुनः प्रस्तुत किया है। जिस कथित पत्र का हमने पहले उल्लेख किया है, उसमें भी आवेदक का नाम नारायण चेतनराम बताया गया है।

इस पत्र में चौधरी और उनकी जन्म तिथि 1 फरवरी 1982 दिखाई गई है। यह पत्राचार 24 जनवरी 2006 को किया गया था। 16. इस न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका में, जिसकी एक प्रति आवेदन के पृष्ठ 40 पर संलग्न की गई है, इसे आधार सी, डी और ई में कहा गया है: -

" ग. इसके लिए वर्तमान याचिकाकर्ता को बहिष्कृत कर दिया गया और

गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसके परिवार ने उसे अस्वीकार कर दिया।

उक्त घटना के साथ संबंध। इसलिए वर्तमान याचिकाकर्ता के पास अपने मामले का बचाव करने का कोई समर्थन या प्रभावी साधन नहीं था। साथ ही

वर्तमान याचिकाकर्ता के पास कोई संकेत देने वाली सामग्री नहीं थी

उसकी असली उम्र।

D. इसके लिए हाल ही में वर्तमान याचिकाकर्ता के पिता ने लगभग 18-19 वर्षों के अंतराल के बाद उनके साथ फिर से संपर्क स्थापित किया

याचिकाकर्ता प्रस्तुत करें। अपने पिता से वर्तमान याचिकाकर्ता को पहली बार घटना के समय अपनी वास्तविक उम्र का संकेत देने के लिए दस्तावेज प्राप्त हुए। वर्तमान याचिकाकर्ता अपने मामले को साबित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों पर भरोसा करना चाहता है।

आई. ' पारिवारिक कार्ड '-राजस्थान राज्य द्वारा वर्तमान याचिकाकर्ता के पिता को जारी किया गया, दिनांक 17.2.1992 जो

वर्तमान याचिकाकर्ता का नाम 'निराना' के रूप में दर्ज करें और

उनकी उम्र 12 वर्ष है।

नारायण चेतनराम चौधरी बनाम। महाराष्ट्र राज्य [अनिरुद्ध बोस, जे.]

ii. स्थानांतरण प्रमाणपत्र-शिक्षा द्वारा जारी किया गया

विभाग, राजस्थान जो नाम दर्ज करता है

याचिकाकर्ता को 'निरनाराम' के रूप में प्रस्तुत करें और उसकी जन्म तिथि है

1.2.1982 के रूप में दर्ज किया गया।

iii. '। राशन कार्ड '-राजस्थान राज्य द्वारा जारी किया गया

वर्तमान याचिकाकर्ता के पिता जो नाम दर्ज करते हैं

वर्तमान याचिकाकर्ता 'निरनाराम' के रूप में।

ई. इसके लिए उपर्युक्त दस्तावेजों से यह बन जाता है

स्पष्ट करें कि वर्तमान याचिकाकर्ता का नाम 'निरनाराम' है और

वर्तमान याचिकाकर्ता की आयु 12 वर्ष थी। इसलिए वर्तमान याचिकाकर्ता को किशोर अपराधी के रूप में माना जाना चाहिए और

इसलिए नियमित परीक्षण में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। "

(पेपरबुक से शब्दशः उद्धृत)

17. यह रिट याचिका 2 जुलाई 2013 को दायर की गई थी, जिसका समर्थन एक

8 अप्रैल 2013 को एक मुखराम का शपथ पत्र। उस हलफनामे में, मुखराम ने खुद को याचिकाकर्ता का छोटा भाई बताया।

हालाँकि इस रिट याचिका पर इस न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया था, हम यह प्रदर्शित करने के लिए रिट याचिका के इस भाग का उल्लेख कर रहे हैं कि कैसे आवेदक ने अपना प्रतिनिधित्व निरनाराम के रूप में करना या फिर से प्रस्तुत करना शुरू किया। इस रिट याचिका में वर्तमान आवेदक ने खुद को चेतनराम चौधरी के बेटे नारायण उर्फ निरनाराम के रूप में वर्णित किया है और वर्तमान आवेदन में आवेदक का वर्णन करने के लिए इसी नाम का उपयोग किया गया है। सत्र न्यायालय (1994 का सत्र मामला No.462) के फैसले में अभियुक्त नं. 1 नारायण चेतनराम चौधरी के रूप में वर्णित किया गया है। इस प्रकार, हम पाते हैं कि उन्होंने अपने मुकदमे के समय चेतनराम के नाम का उपयोग अपने मध्य नाम के रूप में किया था, जो स्पष्ट रूप से उनके पिता के नाम को संदर्भित करता है। वह अपने पिता के नाम का वर्णन करने में निरंतर रहे हैं। अब, हमें इस सवाल पर ध्यान देना होगा कि क्या इतने विलंबित स्तर पर खुद को निरनाराम के रूप में प्रस्तुत करने के कार्य को स्वीकार किया जाना है या नहीं। परिच्छेदों में

53 और जाँच रिपोर्ट के 54 में हम पाते हैं कि जाँच न्यायाधीश ने आवेदक के इस रुख को स्वीकार कर लिया था कि नारायण और निरनाराम

एक ही व्यक्ति।

18. आवेदक ने अपनी पहचान निरन्तराम के रूप में स्थापित करने की मांग की है।

दस्तावेजों की एक श्रृंखला पर भरोसा करते हुए जहाँ उनके पिता का नाम चेतनराम के रूप में दिखाया गया है। इनमें स्कूल से उत्पन्न तीन दस्तावेज, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, जलबसार शामिल हैं।

3] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उन्होंने कहा कि संस्थान एक सरकारी स्कूल है। यह राष्ट्रीय प्रतीक के साथ राज्य सरकार के लेटरहेड का उपयोग करता है। इन दस्तावेजों की प्रतियों को जांच रिपोर्ट में "I-1", "I-2" और "I-3" चिह्नित किया गया है। श्री डूंगरगढ़, बीकानेर के तहसीलदार ने भी 10 तारीख का प्रमाण पत्र जारी किया है। अगस्त 2009 में इस प्रभाव से कि निरनाराम जलबसार का वास्तविक निवासी है और उसे उसमें चेतनराम के पुत्र के रूप में संदर्भित किया गया है। आवेदक के पिता का नाम भी ओ. बी. सी. प्रमाण पत्र में आता है।

जिसे आवेदन में "I-5" चिह्नित किया गया है। यह प्रमाण पत्र भी 10 अगस्त 2009 का है। रुद्रसर ग्राम पंचायत, श्री डूंगरगढ़ की सरपंचा, गौरादेवी के एक प्रमाण पत्र में लिखा है कि नारायण चौधरी वही व्यक्ति हैं जो निरनाराम हैं। इसके बाद, हम जांच न्यायाधीश की रिपोर्ट से पाते हैं कि गौरादेवी और उनके बेटे दोनों ने ऐसा कोई भी प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार कर दिया था। लेकिन उसी रिपोर्ट में, जांच न्यायाधीश द्वारा यह दर्ज किया गया है कि उन्होंने उक्त प्रमाण पत्र में दिखाई देने वाले गौरादेवी के हस्ताक्षर का दूसरे दस्तावेज में उनके हस्ताक्षर के साथ मिलान किया था और उन्हें समान पाया था। यह अनुच्छेद से प्रकट होता है

50 रिपोर्ट जो हमने ऊपर उद्धृत की है। चेतनराम के परिवार कार्ड में, जो रिपोर्ट में "एल-आई" का अनुलग्नक है, 'अनादा', 'मुखराम' और 'निराना' को उनके बेटों के रूप में संदर्भित किया गया है। यह भी अलग है

तिथियाँ। वर्ष 1989 जारी करने की तारीख प्रतीत होती है जबकि

निरीक्षण तिथियाँ 22 सितंबर 1991 और 17 फरवरी 1992 को दर्शाती हैं। उक्त कार्ड में आवेदक की आयु 12 वर्ष दर्शाई गई है। इस प्रकार, स्कूल रिकॉर्ड के साथ पारिवारिक कार्ड में आवेदक की आयु में भिन्नताएं दिखाई देती हैं और हम इस निर्णय में बाद में उस पहलू पर विचार करेंगे। हम यहां इन दस्तावेजों का उल्लेख मुख्य रूप से आवेदक के इस दावे की जांच करने के लिए कर रहे हैं कि वह चेतनराम का पुत्र है। राजू (उपरोक्त) के मामले में, यह देखा गया है कि प्रमाण पत्र पर पिता का नाम दो नामों वाले व्यक्ति की पहचान करने के लिए एक कारक हो सकता है

तैरते हुए। अनादा और मुखराम के दो स्थानांतरण प्रमाणपत्रों (रिपोर्ट के अनुलग्नक एल-2 और एल-3) में भी उनके पिता के रूप में चेतनराम का नाम है। पुनः, जहाँ तक मुखराम के स्थानांतरण प्रमाणपत्र का संबंध है, इसकी मौलिकता के बारे में संदेह है। लेकिन हम पाते हैं कि इन सभी दस्तावेजों में अंद्राम, मुखराम और निरनाराम के पिता के रूप में चेतनराम का निरंतर और सुसंगत संदर्भ दिखाई देता है।

19. राज्य ने एक याचिका दायर की है कि जांच के समय, इस तथ्य को सत्यापित करने के लिए उनके पास पर्याप्त समय नहीं था। कई हैं। जिन दस्तावेजों में निरनाराम को चेतनराम का पुत्र दिखाया गया है। 2019 में जाँच रिपोर्ट बनाए जाने के बाद, मामले की सुनवाई के बाद से काफी समय बीत चुका है। नारायण चेतनराम चौधरी बनाम को राज्य द्वारा कोई सामग्री का उत्पादन नहीं किया गया था।

महाराष्ट्र राज्य [अनिरुद्ध बोस, जे.]

20. जहां तक 2015 के अधिनियम की धारा 9 (2) के तहत वर्तमान आवेदन की स्थिरता का संबंध है, हरि राम-बनाम-राजस्थान राज्य और एक अन्य [(2009) 13 एस. सी. सी. 211] के मामले में, जिसे अब्दुल रज्जाक-बनाम-उत्तर प्रदेश राज्य [(2015) 15 एस. सी. सी. 637] में अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किशोरता का दावा किसी भी न्यायालय के समक्ष उठाया जा सकता है जिसे किसी भी स्तर पर मान्यता दी जाएगी। मामले के अंतिम निपटारे के बाद विनोद कटारा-बनाम-उत्तर प्रदेश राज्य [2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1204] में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने किशोरावस्था के विलंबित दावे को उठाने के तर्क को समझाया है। हरि राम (ऊपर) और अब्दुल रज्जाक (ऊपर) 2000 के अधिनियम के तहत दिए गए निर्णय थे, लेकिन जहां तक 2015 के अधिनियम का संबंध है,

वही सिद्धांत लागू होना चाहिए। इसके अलावा, 2015 के अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) के प्रावधान में, यह विशेष रूप से निर्धारित किया गया है कि -

किशोरता का दावा किसी भी न्यायालय के समक्ष उठाया जा सकता है और मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी किसी भी स्तर पर इसे मान्यता दी जाएगी। तर्क की एक ही रेखा

राम नारायण-बनाम-उत्तर प्रदेश राज्य [(2015) 17 एस. सी. सी. 699] और उपेंद्र प्रधान-बनाम-स्टे के मामलों में इसका पालन किया गया है।

उड़ीसा [(2015) 11 एससीसी 124]। राज्य ने इस स्तर पर न्यायालय के हस्तक्षेप का विरोध करते हुए इस बिंदु पर पवन कुमार गुप्ता (उपरोक्त) के मामले पर भरोसा किया है। उस मामले में अभियुक्त ने जाँच अधिकारी द्वारा दी गई आयु निर्धारण रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था और यह मामले में दर्ज किया गया था।

संबंधित मजिस्ट्रेट का आदेश। उक्त रिपोर्ट के अनुसार आरोपी नाबालिग नहीं था। वही याचिका अपीलिय [2023] 6 एस. सी. आर. में फिर से उठाई गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिसे मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश का हवाला देते हुए खारिज कर दिया गया था। इस न्यायालय के समक्ष पुनर्विचार याचिका के संबंध में, किशोरता की याचिका फिर से उठाई गई थी, और इस न्यायालय द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया था। उक्त निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक बार मजिस्ट्रेट, उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय के स्तर से किशोरता की याचिका खारिज हो जाने के बाद, दोषी को उस याचिका को फिर से दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। आवेदक के मामले में, इस अदालत के समक्ष पहली बार किशोरता याचिका दायर की गई है, हालांकि इस अदालत द्वारा उसकी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ उसकी समीक्षा याचिका खारिज किए जाने के बाद इसे बरकरार रखा गया है।

21. यह एक तथ्य है कि किशोरता याचिका 2013 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 126 में उठाई गई थी और इस रिट याचिका को सीमित रूप से खारिज कर दिया गया था। लेकिन जहां तक वर्तमान आवेदन का संबंध है, यह बर्खास्तगी न्यायिक प्रक्रिया के रूप में कार्य नहीं करेगी। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत राहत प्रकृति में विवेकाधीन है और इस अदालत का उस याचिका को खारिज करने का आदेश कारण से समर्थित नहीं है। 2015 की धारा 9 (2) के तहत एक याचिका अधिनियम सांविधिक उपचार पर विचार करता है, जिसके लिए किसी भी स्तर पर याचिका दायर की जा सकती है। हमारी राय में, किशोरता याचिका पर, यदि एक रिट याचिका खारिज कर दी जाती है

सीमित, इस तरह के आदेश एक आरोपी (या एक) के विकल्प को बंद नहीं करेगा

दोषी) 2015 अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) के तहत किशोरता के लिए याचिका दायर करने के लिए।

22. तदनुसार, हम उसके किशोर होने के दावे की जांच करने के लिए आगे बढ़ेंगे, जिसे जांच न्यायाधीश ने उपरोक्त रिपोर्ट में कायम रखा है।

मुरारी ठाकुर (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने एक अपील में किशोरता याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें अपीलार्थियों को 1860 की संहिता की धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था। अपीलीय स्तर पर इस न्यायालय के समक्ष ऐसी याचिका दायर की गई थी। ए टू-जज

इस न्यायालय की पीठ ने राय दी कि इस बिंदु को उस स्तर पर नहीं उठाया जा सकता क्योंकि इसे न तो निचली अदालत के समक्ष लिया गया था और न ही उच्च न्यायालय के समक्ष। इस निर्णय में आगे यह देखा गया कि अपीलार्थी अभियुक्त की आयु का प्रश्न तथ्य का प्रश्न था कि किस साक्ष्य, प्रतिपरीक्षा आदि की आवश्यकता थी और इसलिए इसे अंतिम चरण में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। यह 2000 के अधिनियम के तहत एक मामला था, लेकिन उक्त अधिनियम के तहत भी, इसकी धारा 7 ए के प्रावधान 2015 के अधिनियम की धारा 9 (2) के समान हैं। हमारी राय में, इस दृष्टिकोण को इस अधिनियम में निहित विशिष्ट प्रावधानों के संबंध में अच्छा कानून नहीं माना जा सकता है।

2015 अधिनियम की धारा 9 (2) का प्रावधान। इसके अलावा, अश्वनी कुमार नारायण चेतनराम चौधरी बनाम के मामले में उसी शक्ति की पीठ का एक बाद का निर्णय है।

महाराष्ट्र राज्य [अनिरुद्ध बोस, जे.]

सक्सेना (उपर्युक्त) जिसमें इस न्यायालय ने किशोरावस्था की स्थापना से संबंधित दस्तावेजों की जांच करने के तरीके की जांच की है और हम इस निर्णय में बाद में इस प्राधिकरण से निपटेंगे। अजय कुमार बनाम मध्य प्रदेश राज्य [(2010) 15 एस. सी. सी. 83] के मामले में इस न्यायालय की दो अन्य न्यायाधीशों की पीठ ने 2000 के अधिनियम की धारा 7 ए का हवाला देते हुए कहा है कि उस न्यायालय द्वारा जांच की जानी है जिसके समक्ष ऐसी याचिका दायर की गई है और न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालना होगा कि दावेदार किशोर था या नहीं। इस निर्णय के अनुसार, यदि दावेदार किशोर पाया जाता है, तो अदालत को उचित आदेश पारित करने के लिए मामले को बोर्ड को भेजना होगा और इस तरह के मामले में

स्थिति, न्यायालय द्वारा पारित सजा का कोई प्रभाव नहीं होगा।

23. पवन (ऊपर) में समन्वय शक्ति की एक पीठ ने राय दी कि ऐसे मामले में जहां किशोरावस्था की याचिका अनैतिक या सामग्री पाई जाती है इस तरह की याचिका के समर्थन में विश्वसनीयता की कमी है और विश्वास को प्रेरित नहीं करता है और यहां तक कि न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि भी नहीं की जाती है।

इस तरह के दावे की जांच करने का अभ्यास अनावश्यक होगा। उस फैसले में,

दावा किया जा रहा था और इस तरह के निष्कर्ष पर आया था। जहाँ तक इस मामले का संबंध है, 29 जनवरी 2019 को पारित आदेश में, जिस संदर्भ में जांच का निर्देश दिया गया था, उसे व्यक्त किया गया है। प्रासंगिक भाग इस आदेश का उल्लेख इस निर्णय में पहले किया गया है। इस प्रकार, पवन (उपरोक्त) के मामले में की गई टिप्पणियां इस मामले के तथ्यों में लागू नहीं होती हैं, जहां जांच पहले ही निर्देशित की जा चुकी है।

24. मोहम्मद में। अनवर (ऊपर) और सूरजदेव (ऊपर), (बाद के मामले में, इस फैसले के लेखक एक पक्ष थे), की दो समन्वित पीठें

इस न्यायालय ने राय दी कि किशोरावस्था जैसी परिस्थितियों को कम करने के लिए आमतौर पर मुकदमे में ही उठाया जाना चाहिए और इस तरह की याचिका को देर से उठाना भी बचाव मामले की वास्तविकता की कमी को रेखांकित कर सकता है। सूरजदेव (उपरोक्त) के मामले में, बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रवेश पत्र के साथ-साथ विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र के आधार पर इस न्यायालय के समक्ष पहली बार किशोरता की याचिका दायर की गई थी। अदालत ने पाया कि किशोर दावेदार का नाम दस्तावेजों पर नहीं आया है। लेकिन ये संबंधित मामलों के तथ्यों में दिए गए निर्णय थे और इन दोनों मामलों में से कोई भी कानून के पूर्ण प्रस्ताव को निर्धारित नहीं करता है कि किशोरता याचिका को उस स्तर पर नहीं उठाया जा सकता है जब आवेदक ने 2015 अधिनियम की धारा 9 (2) के तहत अपनी याचिका दायर की है। इसके अलावा, यह न्यायालय पहले ही जांच का निर्देश दे चुका है और हमें नहीं लगता कि आवेदक की याचिका को वर्तमान मामले में विलंबित दावे के आधार पर खारिज किया जा सकता है।

सी आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

25. इसके बाद यह सवाल आता है कि क्या न्यायाधीश द्वारा अपनाया गया पाठ्यक्रम 2015 के अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में था या श्री पाटिल ने 2015 के अधिनियम की धारा 103 पर भरोसा करते हुए कहा कि यह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अनुसार होना चाहिए। 2015 के अधिनियम की धारा 103 में कहा गया है:

" 103. पूछताछ, अपील और पुनरीक्षण में प्रक्रिया

कार्यवाही। — (1) इस अधिनियम, समिति या बोर्ड द्वारा किसी भी जांच के दौरान स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए प्रावधान को छोड़कर

इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत, ऐसी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा जो निर्धारित की जाए और उसके अधीन, समन के मुकदमे के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में निर्धारित प्रक्रिया का, जहां तक हो सके, पालन किया जाएगा।

मामले।

(2) इसके द्वारा या इसके तहत अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए रूप में सहेजें

अधिनियम, अपीलों की सुनवाई में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया या

इस अधिनियम के तहत पुनरीक्षण कार्यवाहियां, जहाँ तक

व्यवहार्य, संहिता के प्रावधानों के अनुसार

दंड प्रक्रिया, 1973 (1974 का 2) "।

जहां तक हमारे द्वारा जांच के माध्यम से उम्र के निर्धारण का सवाल है, कोई विशिष्ट वैधानिक प्रक्रिया हमारे संज्ञान में नहीं लाई गई है। अधिनियम की धारा 94 में निहित वैधानिक प्रावधान में प्रासंगिक हैईगार्ड और उक्त धारा में कहा गया है:

" 94. आयु का अनुमान और निर्धारण। - (1) वह कहाँ है?

समिति या बोर्ड के लिए स्पष्ट, के आधार पर

इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत (साक्ष्य देने के उद्देश्य के अलावा) उसके सामने लाए गए व्यक्ति की उपस्थिति कि उक्त व्यक्ति एक बच्चा है, समिति या बोर्ड इस तरह के अवलोकन को दर्ज करेगा जिसमें कहा गया है कि उसकी आयु कितनी है।

बच्चा जितना हो सके उतना करीब है और धारा 14 या धारा 36 के तहत बिना प्रतीक्षा किए जांच के साथ आगे बढ़ता है।

आयु की और पुष्टि के लिए।

(2) यदि समिति या बोर्ड के पास उचित है

इस बारे में संदेह का आधार कि क्या व्यक्ति लाया गया था

इससे पहले कि वह बच्चा हो या न हो, समिति या बोर्ड, जैसा भी मामला हो, आयु निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करेगा।

नारायण चेतनराम चौधरी बनाम को प्राप्त करके साक्ष्य की मांग करके।

महाराष्ट्र राज्य [अनिरुद्ध बोस, जे.]

(i) स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र की तारीख, या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो; और उसके अभाव में;

((ii) किसी निगम या संस्था द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र।

(iii) और केवल (i) और (ii) से ऊपर की अनुपस्थिति में, आयु का निर्धारण एक अस्थिरकरण परीक्षण या किसी अन्य नवीनतम द्वारा किया जाएगा। के आदेश पर आयोजित चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण

समिति या बोर्ड:

बशर्ते कि समिति या बोर्ड के आदेश पर आयोजित ऐसी आयु निर्धारण परीक्षा ऐसे आदेश की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर पूरी की जाएगी।

(3) समिति या बोर्ड द्वारा अभिलिखित आयु

इस प्रकार उसके समक्ष लाए गए व्यक्ति की आयु, इस उद्देश्य के लिए होगी -

इस अधिनियम को उस व्यक्ति की वास्तविक आयु माना जाएगा।

26. राज्य की ओर से एक तर्क यह रहा है कि

27. यह स्पष्ट है कि जांच न्यायाधीश ने जांच आमतौर पर एक तथ्य-निष्कर्ष जांच के रूप में की है और इसका पालन नहीं किया है समन विचारण की प्रक्रिया। जिन दस्तावेजों पर उन्होंने भरोसा किया था, वे औपचारिक रूप से साबित नहीं हुए थे जैसा कि एक मुकदमे में सामान्य प्रक्रिया है और शपथ पर कोई जांच या प्रतिपरीक्षा नहीं थी। लेकिन जैसा कि 2015 के अधिनियम की धारा 103 की उप-धारा (1) से स्पष्ट होगा, समन मामलों में प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश किशोर न्याय के लिए है।

बोर्ड ("बोर्ड") या बाल कल्याण समिति ("समिति") 2015 के अधिनियम के तहत कोई भी जांच करते समय। 2015 के अधिनियम की धारा 9 (2) के तहत अदालत को यह जांच करने का भी अधिकार दिया गया है कि क्या अदालत की खुद यह राय है कि वह व्यक्ति अपराध करने की तारीख को बच्चा था। समन प्रक्रिया का पालन करने का आदेश

अब तक ऐसी जांच निर्धारित नहीं की गई है जो [2023] 6 एस. सी. आर. द्वारा की जानी चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अदालत द्वारा। जिस तरीके से सबूत लिया जा सकता था, उसे अनिवार्य नहीं किया गया है। जिस तरीके से न्यायालय इस तरह की जांच करेगा, वह भी विशेष रूप से निर्धारित नहीं किया गया है। वर्तमान मामले में इस न्यायालय द्वारा जिस प्रक्रिया का पालन किया गया है, वह एक प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश, राज्य स्तर पर एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी को एक निश्चित समय सीमा के भीतर जांच करने का निर्देश देना है। जैसा कि हम जाँच रिपोर्ट से पाते हैं, जाँच न्यायाधीश ने एक पुलिस अधिकारी को निर्देश दिया था कि आवेदक द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों का प्रमाणीकरण और पुलिस अधिकारी द्वारा दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर अपने विचार देने के बाद, उनमें से कुछ में विसंगति पाई गई। इसके बाद, जांच न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई की गई, जिसमें अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व पुलिस महानिदेशक ("डीजीपी") के पद पर आसीन एक अधिकारी द्वारा किया गया। अभियोजन पक्ष और पुलिस दोनों ने जांच न्यायाधीश के समक्ष रिपोर्ट और बयान दायर किया था। जाँचकर्ता न्यायाधीश ने स्वयं अभियोजन पक्ष के साथ-साथ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों पर विचार करते हुए अपना दिमाग लगाया और आवेदक को स्वयं जाँचकर्ता न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया। जाँचकर्ता न्यायाधीश ने उनके सामने दाखिल किए गए दस्तावेजों को प्रदर्शन के रूप में चिह्नित किया था। जाँच करने वाले न्यायाधीश ने डी. जी. पी. और आवेदक का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील के रुख का पता लगाने पर प्रत्येक दस्तावेज की जाँच की। हमारे समक्ष दायर आवेदन में, स्कूल रजिस्टर से उद्धरण संलग्न किया गया था जिसमें आवेदक की जन्म तिथि 1 फरवरी 1982 दिखाई गई थी। जाँचकर्ता न्यायाधीश के समक्ष, हम पाते हैं कि आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों के अलावा, स्कूल प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र भी आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बाद वाला स्कूल रजिस्टर के आधार पर जारी किया गया था लेकिन यह प्रमाण पत्र 30 जनवरी 2019 का था।

28. हम जांच न्यायाधीश द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। जहाँ तक न्यायालय द्वारा जाँच करने की प्रक्रिया की बात है, हमारी राय में 2015 के अधिनियम की धारा 9 (2) 1973 की संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में निर्धारित परीक्षण प्रक्रिया का ईमानदारी से पालन करने का निर्देश नहीं देती है। 2015 के अधिनियम की धारा 9 में कहा गया है:

" 9. एक मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जिसे इस अधिनियम के तहत अधिकार नहीं दिया गया है। - (1) जब एक मजिस्ट्रेट, इस के तहत बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त नहीं है
अधिनियम की राय है
कि अपराध करने का आरोप लगाने वाला और उसके सामने लाया गया व्यक्ति एक बच्चा है, वह बिना किसी देरी के ऐसी राय दर्ज करेगा और बच्चे को आगे बढ़ाएगा।

ऐसी कार्यवाहियों के अभिलेख के साथ तुरंत

अधिकार क्षेत्र वाला बोर्ड।

नारायण चेतनराम चौधरी बनाम। महाराष्ट्र राज्य [अनिरुद्ध बोस, जे.]

(2) यदि किसी व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप लगाया जाता है

बोर्ड के अलावा किसी अन्य अदालत के समक्ष दावा करता है कि व्यक्ति अपराध करने की तारीख को बच्चा है या बच्चा था, या यदि अदालत की खुद यह राय है कि वह व्यक्ति एक था अपराध करने की तारीख को, उक्त अदालत एक जांच करेगी, ऐसा सबूत लेगी जो आवश्यक हो।

(लेकिन एक हलफनामा नहीं) ऐसे व्यक्ति की उम्र निर्धारित करने के लिए, और मामले पर एक निष्कर्ष दर्ज करेगा, जिसमें उम्र का उल्लेख होगा

व्यक्ति जितना हो सके उतना करीब:

इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार, भले ही व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उससे पहले बच्चा नहीं रहा हो।
(3) यदि अदालत को पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और ऐसा अपराध करने की तारीख को वह बच्चा था, तो वह बच्चे को उचित पारित करने के लिए बोर्ड को भेजेगी।

न्यायालय द्वारा पारित आदेश और सजा, यदि कोई हो,

(4) यदि इस धारा के तहत किसी व्यक्ति को सुरक्षात्मक हिरासत में रखने की आवश्यकता है, जबकि उस व्यक्ति के बच्चे होने के दावे की जांच की जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति को हिरासत में रखा जा सकता है।
सुरक्षा के स्थान पर
हस्तक्षेप की अवधि।

किशोर दावेदार के निर्धारण ने न्यायालय द्वारा जांच के लिए किसी विशिष्ट प्रक्रिया को अनिवार्य नहीं किया है। इसका तात्पर्य यह है कि न्यायालय इस संबंध में जांच करने के लिए अपनी प्रक्रिया तैयार कर सकता है। जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है, इस न्यायालय ने पहले स्तर पर जांच न्यायाधीश द्वारा जांच करने का निर्देश दिया था, जिनके समक्ष आवेदक और अभियोजन पक्ष को पर्याप्त अवसर था उनका संस्करण प्रस्तुत करें। जांच न्यायाधीश की रिपोर्ट की बाद में हमारे द्वारा जांच की गई, जिससे दोनों पक्षों को फिर से पर्याप्त अवसर मिला। हमने स्वयं स्कूल से मूल प्रवेश रजिस्टर माँगा है। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका-प्रभारी नम्रता प्रभुसिंह ने एक [2023] 6 एस. सी. आर. दिया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जाँच स्तर पर लिखित रूप में नहीं, और 'एन' का अनुवादित संस्करण जाँच रिपोर्ट के पृष्ठ 311 पर दिखाई देता है। उन्होंने कहा है:

" उपरोक्त के संदर्भ में, निरनाराम एस/ओ का नाम

चेतनराम, जलबसार को स्टूडेंट में दर्ज किया गया है।

हमारे राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक का प्रवेश रजिस्टर

स्कूल, जलबसार, श्रीदनगरगढ़ में छात्र प्रवेश संख्या।

568. उक्त अभिलेख के अनुसार, उनकी जन्म तिथि है - 01.02.1982 के रूप में लिखा गया। नारायण नाम का कोई छात्र नहीं था।

हमारा स्कूल। "

(पेपरबुक से शब्दशः उद्धृत)

29. अश्विनी कुमार सक्सेना (ऊपर) मामले में दो-न्यायाधीशों की पीठ

टी, 2000 अधिनियम के प्रावधानों से निपटने के लिए देखा गया और अभिनिर्धारित किया गया:

" 25. धारा 7-ए, न्यायालय को केवल जांच करने के लिए बाध्य करती है,

न जांच या मुकदमा, न जांच संहिता के तहत दंड प्रक्रिया के तहत, लेकिन जेजे अधिनियम के तहत। द क्रिमिनल

अदालतें, किशोर न्याय बोर्ड, समितियाँ, आदि हमारे पास हैं नोटिस किया, आगे बढ़ें जैसे कि वे एक परीक्षण, जांच कर रहे हैं,

जे. जे. में जांच करने का तरीका प्रदान किया गया है। नियम। धारा 7-ए और नियम में प्रयुक्त कुछ अभिव्यक्तियाँ

12 इनका काफी महत्व है और उनका एक संदर्भ है

इनके वास्तविक दायरे और विषय-वस्तु को समझना आवश्यक है।

प्रावधान। धारा 7-ए ने इन अभिव्यक्तियों का उपयोग किया है "न्यायालय करेगा

जाँच करें ", " ऐसा सबूत लें जो आवश्यक हो "

और "लेकिन एक शपथ पत्र नहीं"। न्यायालय या बोर्ड स्वीकार कर सकता है। एक हलफनामे से कुछ अधिक सबूत के रूप में अर्थात् न्यायालय

साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य होने की आवश्यकता नहीं है।
पढ़ा जाना है

26. नियम 12 जिसे धारा 7-ए के साथ

कुछ अभिव्यक्तियों का भी उपयोग किया जाता है जिन्हें भी वहन किया जाना है

दिमाग। नियम 12 (2) "प्रथम दृष्टया" और "पर" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है। भौतिक
उपस्थिति या दस्तावेजों का आधार, यदि

उपलब्ध "। नियम 12 (3) में "मांग करके" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है।

इस तथ्य पर जोर दें कि धारा 7-ए में क्या विचार किया गया है और नियम 12 केवल एक जांच
है। इसके अलावा, आयु निर्धारण रायन चेतनराम चौधरी बनाम।

महाराष्ट्र राज्य [अनिरुद्ध बोस, जे.]

आवेदन करने की तारीख से तीस दिनों के भीतर जांच पूरी की जानी चाहिए और उम्र निर्धारित की जानी चाहिए; जो इस बात का भी संकेत है कि जांच कैसे की जानी है और कैसे पूरी की जानी है। जे. जे. अधिनियम के तहत "जांच" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन जे. जे. अधिनियम की धारा 2 (वाई) में कहा गया है कि जे. जे. अधिनियम में उपयोग किए गए और परिभाषित नहीं किए गए, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में परिभाषित किए गए सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ उस संहिता में क्रमशः दिए गए होंगे।

27. आइए अब हम "जांच", "जांच", "जांच" और "परीक्षण" शब्दों के अर्थ की जांच करें जैसा कि हम दंड प्रक्रिया संहिता में देखते हैं और उनके कई अर्थों को जिम्मेदार ठहराते हैं।

उन अभिव्यक्तियों के लिए "। सी. आर. पी. सी. की धारा 2 (जी) में परिभाषित "जांच" इस प्रकार है:

" 2. (छ) "जांच" से मजिस्ट्रेट या अदालत द्वारा इस संहिता के तहत की गई मुकदमे के अलावा प्रत्येक जांच अभिप्रेत है।

"पूछताछ" शब्द को दंड प्रक्रिया संहिता के तहत परिभाषित नहीं किया गया है जो जानकारी मांगने और कुछ सबूतों पर विचार करने का एक कार्य है, जो दस्तावेजी हो सकता है।

" सी. आर. पी. सी. की धारा 2 (एच) में परिभाषित "जांच" इस प्रकार है

निम्नलिखित है:

" 2. (ज) 'जाँच' में पुलिस द्वारा किए गए साक्ष्य के संग्रह के लिए इस संहिता के तहत सभी कार्यवाही शामिल हैं।

अधिकारी या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा (मजिस्ट्रेट के अलावा) जो इस संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत हो;

दंड प्रक्रिया संहिता में "मुकदमा" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसे "जांच" या "जांच" शब्दों के आलोक में समझा जाना चाहिए जैसा कि इसमें निहित है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (जी) और 2 (एच)।

28. "विचारण" शब्द को आम तौर पर किए गए कुछ अपराधों से संबंधित निर्णय देने के उद्देश्य से किसी मामले में तथ्य और कानून के मुद्दों की अदालत द्वारा परीक्षा के रूप में समझा गया है। हम बहुत से मामलों में पाते हैं कि अदालत/किशोर न्याय बोर्ड के दावे का निर्धारण करते समय किशोरावस्था यह भूल जाती है कि उनसे अपराधिक संहिता [2023] 6 एस. सी. आर. की धारा 2 (जी) के तहत जांच नहीं करने की अपेक्षा की जाती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रक्रिया, लेकिन जे. जे. अधिनियम के तहत एक जांच, नियम 12 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए और संहिता के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए।

29. संहिता प्रत्येक में पालन की जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करती है।

प्रत्येक अपराध के लिए जांच, जांच या मुकदमा, चाहे वह दंड संहिता के तहत हो या अन्य दंडात्मक कानूनों के तहत। संहिता न केवल अपराधों की जांच, जांच या मुकदमे के लिए प्रावधान करती है, बल्कि कुछ विशिष्ट मामलों की जांच के लिए भी प्रावधान करती है। संहिता के तहत विशिष्ट मामलों की जांच के लिए निर्धारित प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से 2007 के नियमों के नियम 12 के साथ पठित धारा 7-ए के तहत किशोरता के दावे जैसे अन्य मामलों की जांच में लागू नहीं की जा सकती है। दूसरे शब्दों में, ऐसी जांच में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में कानून जांच करने के लिए अधिकार क्षेत्र प्रदान करने वाले अधिनियम में पाया जाना चाहिए।

30. नतीजतन, जेजे के तहत अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

जांच करने में अधिनियम वह प्रक्रिया है जो उस कानून में ही निर्धारित की गई है अर्थात् 2007 के नियमों के नियम 12 में। हम दंड संहिता में निर्धारित अन्य प्रक्रियाओं को लागू नहीं कर सकते हैं।

जाँच करते समय प्रक्रिया या कोई अन्य अधिनियम

किसी व्यक्ति की किशोरता के संबंध में, जब अधिनियम की धारा 7-ए के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय के समक्ष किशोरता का दावा किया जाता है। कई मामलों में, हमने देखा है कि यह देखा गया है कि आपराधिक अदालतों में अभी भी संहिता के तहत मुकदमे या जांच की प्रक्रिया को लटकाया जा रहा है

मानो वे दंडात्मक कानूनों के तहत किसी अपराध का मुकदमा चला रहे हैं, इस तथ्य को भूलकर कि विशिष्ट प्रक्रिया में निर्धारित किया गया है

धारा 7-ए को नियम 12 के साथ पढ़ा जाता है।

31. हम सभी अदालतों/किशोर न्याय बोर्डों और अधिनियम के तहत काम करने वाली समितियों को यह भी याद दिलाते हैं कि उन पर नियम 12 (3) (ए) (आई) से (iii) में उल्लिखित प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करके साक्ष्य प्राप्त करने का कर्तव्य है। ऐसी स्थितियों में अदालतें माता-पिता के संरक्षक के रूप में कार्य करती हैं क्योंकि वे दयालु होते हैं।

उन नाबालिगों पर संरक्षकता जो अपनी कानूनी अक्षमता से हैं

सुरक्षा की आवश्यकता है।

32. " 2007 के नियमों के नियम 12 के साथ पठित अधिनियम की धारा 7-ए के तहत विचार की गई आयु निर्धारण जांच रायन चेतनराम चौधरी बनाम को सक्षम बनाती है।

महाराष्ट्र राज्य [अनिरुद्ध बोस, जे.]

अदालत सबूत मांगने के लिए और उस प्रक्रिया में, अदालत कर सकती है

यदि उपलब्ध हो तो मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र प्राप्त करें। केवल किसी भी मैट्रिक या समकक्ष के अभाव में प्रमाणपत्र, अदालत को जन्म तिथि प्राप्त करने की आवश्यकता है

स्कूल से प्रमाण पत्र पहली बार एक प्ले स्कूल के अलावा अन्य में भाग लिया। केवल मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र या पहली बार उपस्थित स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति में, अदालत को निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

(शपथ पत्र नहीं बल्कि प्रमाण पत्र या दस्तावेज)। विधिवत गठित चिकित्सा से चिकित्सा राय प्राप्त करने का प्रश्न

बोर्ड तभी बनता है जब उपर्युक्त दस्तावेज उपलब्ध न हों। यदि आयु का सटीक आकलन नहीं किया जा सकता है, तो न्यायालय, दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, यदि - आवश्यक समझे जाने पर, बच्चे या किशोर को लाभ सीमा के भीतर निचली तरफ उसकी उम्र पर विचार करके दें।

एक वर्ष की।

33. एक बार जब अदालत, उपर्युक्त प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, एक आदेश पारित करती है, तो वह आदेश कानून के साथ संघर्ष में ऐसे बच्चे या किशोर के संबंध में उम्र का निर्णायक प्रमाण होगा। नियम 12 के उप-नियम (5) में यह स्पष्ट किया गया है कि अदालत या बोर्ड द्वारा आगे कोई जांच नहीं की जाएगी।

नियम 12 के उप-नियम (3) का उल्लेख करने के बाद दस्तावेजी प्रमाण। इसके अलावा, जेजे अधिनियम की धारा 49 भी इसके निर्धारण पर किशोरावस्था की आयु का अनुमान लगाती है। 34. जेजे अधिनियम और 2007 के नियमों के तहत विचार की गई आयु निर्धारण जांच का इसके तहत की गई जांच से कोई लेना-देना नहीं है।

अन्य कानून, जैसे सेवा में प्रवेश, सेवानिवृत्ति, पदोन्नति आदि। ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ प्रविष्टि की गई हो

मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, जन्म तिथि

स्कूल से पहले उपस्थित होने का प्रमाण पत्र और यहां तक कि निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र भी सही नहीं हो सकता है। लेकिन अदालत, किशोर न्याय जेजे अधिनियम के तहत काम करने वाले बोर्ड या समिति से इस तरह की जांच करने और उन प्रमाणपत्रों की शुद्धता की जांच करने के लिए पीछे जाने की उम्मीद नहीं की जाती है

व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम के दौरान रखे गए दस्तावेज।

[2023] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ऐसे मामलों में जहां उन दस्तावेजों या प्रमाणपत्रों को मनगढ़ंत या हेरफेर किया गया पाया जाता है, अदालत, किशोर न्याय बोर्ड या समिति को आयु के लिए चिकित्सा रिपोर्ट देने की आवश्यकता होती है

दृढ़ संकल्प।

30. अश्विनी कुमार सक्सेना (ऊपर) के मामले को इस न्यायालय के कई फैसलों में संदर्भित किया गया है और इसका अनुपात अभी भी अच्छा है। हालाँकि यह 2000 के अधिनियम के तहत दिया गया एक निर्णय था, 2015 के अधिनियम में किशोरता निर्धारित करने की प्रक्रिया व्यापक रूप से समान है और इसलिए यह प्राधिकरण 2015 के अधिनियम के तहत जांच के लिए मान्य रहेगा। शिव मंगल सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1989) एस. सी. सी. ऑनलाइन ऑल 605] के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ पीठ) के एकल न्यायाधीश का एक निर्णय है जिसमें 1986 के अधिनियम से निपटने के लिए यह विचार लिया गया है कि उसमें धारा 3 में "जांच" शब्द का अर्थ उक्त अधिनियम के तहत जांच है न कि

1973 की संहिता के तहत जांच। 1986 के अधिनियम की धारा 2 (टी) में 2015 के अधिनियम की धारा 103 के समान प्रावधान किए गए थे। जिस तरह से 1973 की संहिता में "जांच" शब्द का उपयोग किया गया है, उसे 2015 के अधिनियम के संबंध में पूरी तरह से प्रत्यारोपित नहीं किया जा सकता है, ताकि जांच के अर्थ के अनुरूप हो सके। इसमें 2015 के अधिनियम के तहत खोज या जांच का एक तत्व है, इस अर्थ में नहीं कि इन शब्दों का उपयोग 1973 की संहिता के अध्याय XXIII और XXIV में किया गया है, जिसे न्यायालय कर सकता है। किशोरता दावे का निर्धारण करते समय कार्य करने की आवश्यकता होती है। 1973 की संहिता की धारा 148 और 174 के तहत प्रारंभिक जांच पर भी विचार किया गया है।

संहिता और उक्त अभिव्यक्ति का उपयोग 1973 की संहिता में एक समान अर्थ या प्रक्रिया व्यक्त करने के लिए नहीं किया गया है। हमारा मानना है कि

अश्विनी कुमार सक्सेना (उपरोक्त) के मामले में "जांच" शब्द का अर्थ और दायरा इस शब्द का उचित निर्माण है और 2015 के अधिनियम के तहत किशोर दावे के निर्धारण के प्रश्न से निपटने में इसका पालन किया जा सकता है। श्री पाटिल ने तर्क दिया है कि अबुज़र हुसैन के मामले में इस अदालत के फैसले के कारण अश्विनी कुमार सक्सेना (उपरोक्त) के मामले में अनुपात कम हो गया होगा।

(ऊपर), तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया। लेकिन अबुज़र हुसैन (ऊपर) उस संदर्भ से संबंधित है जिसमें 2000 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत जांच का निर्देश दिया जाएगा। यह प्राधिकरण अश्विनी कुमार सक्सेना (उपरोक्त) के मामले में निर्णय के अनुपात के साथ टकराव में नहीं आता है, जिस हद तक बाद का निर्णय 2000 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत "जांच" अभिव्यक्ति के अर्थ और निहितार्थ को समझता है। इस तरह की जांच का उद्देश्य स्पष्ट रूप से दावेदार की किशोरता का निर्धारण करना है। जहाँ तक 2015 के अधिनियम की धारा 94 का संबंध है, हालाँकि नारायण चेतनराम चौधरी बनाम।

महाराष्ट्र राज्य [अनिरुद्ध बोस, जे.]

उक्त प्रावधान समिति या बोर्ड द्वारा एक किशोर-दावेदार की उम्र के निर्धारण से संबंधित है, हमारी राय में उसमें निर्दिष्ट दस्तावेज या परीक्षण अदालत को ऐसी प्रकृति की जांच करने में भी मार्गदर्शन करेंगे। न्यायालय को उक्त अधिनियम की धारा 9 (2) के तहत जांच करने के संबंध में किसी विशिष्ट विधायी आदेश के अभाव में, धारा 94 (2) के प्रावधानों का प्रिस्क्रिप्शन एक सुरक्षित मार्गदर्शन प्रदान करता है जिसका न्यायालय को पालन करना चाहिए। न्यायालय द्वारा घोषित ऐसी जांच का परिणाम दावेदार-अभियुक्त की किशोरता पर घोषणा की प्रकृति का होगा।

31. ऋषिपाल सिंह सोलंकी-बनाम-उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [(2022) 8 एस. सी. सी. 602] के मामले में, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने इस विषय पर मामलों के एक बड़े समूह पर विचार करते हुए यह विचार व्यक्त किया और कहा: -

" 33. के संचयी विचार पर क्या उभरता है

उपरोक्त निर्णयों का विवरण इस प्रकार है:

33.1 . किशोरावस्था का दावा किसी भी स्तर पर उठाया जा सकता है।

आपराधिक कार्यवाही, मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी। किशोरावस्था के दावे को उठाने में देरी इस तरह के दावे को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती है। इसके लिए भी उठाया जा सकता है

इस न्यायालय के समक्ष पहली बार।

33.2 . किशोरावस्था का दावा करने वाला आवेदन किया जा सकता है।

या तो अदालत या जेजे बोर्ड के समक्ष।

33.2. 1 . जब किशोरावस्था का मुद्दा अदालत के समक्ष आता है, तो यह जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 9 की उप-धाराओं (2) और (3) के तहत होगा, लेकिन जब किसी व्यक्ति को अदालत के समक्ष लाया जाता है। समिति या जेजे बोर्ड, जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94 लागू होती है।

33.2. 2 . यदि किशोर होने का दावा करते हुए अदालत के समक्ष कोई आवेदन दायर किया जाता है, तो जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94 की उप-धारा (2) के प्रावधान को लागू करना होगा या साथ में पढ़ना होगा। धारा 9 की उप-धारा (2) के साथ ताकि आयु बताते हुए निष्कर्ष दर्ज करने के उद्देश्य से साक्ष्य प्राप्त किया जा सके

व्यक्ति जितना हो सके उतना करीब हो।

33.2. 3 . जब जे. जे. बोर्ड के समक्ष जे. जे. अधिनियम, 2015 की धारा 94 के तहत नाबालिग होने का दावा करने वाला आवेदन किया जाता है, जब मामला [2023] 6 एस. सी. आर. के कथित कमीशन के संबंध में होता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपराध एक अदालत के समक्ष लंबित है, फिर प्रक्रिया के तहत विचार किया जाएगा

जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94

आवेदन करें। उक्त प्रावधान के तहत यदि जेजे बोर्ड के पास है उचित आधार

व्यक्ति के बारे में संदेह के लिए

उसके सामने लाया गया कि वह बच्चा है या नहीं, बोर्ड करें

मांग करके आयु निर्धारण की प्रक्रिया शुरू

जे. जे. बोर्ड द्वारा दर्ज साक्ष्य और आयु

जे. जे. बोर्ड के समक्ष, जब मुकदमा संबंधित आपराधिक अदालत के समक्ष होता है, तब किशोरावस्था के दावे के लिए आवेदन दायर किया जाता है, तब जांच की तुलना में अधिक होता है। एक अदालत द्वारा जिसके समक्ष अपराध करने के संबंध में मामला लंबित है (जेजे अधिनियम की धारा 9 के अनुसार,

2015) .

33.3 . कि जब किशोरावस्था का दावा किया जाता है, तो बोर्ड

प्रारंभिक बोर्ड के निर्वहन के लिए अदालत को संतुष्ट करने का दावा करने वाले व्यक्ति पर है। हालांकि, दस्तावेज

जेजे अधिनियम, 2000 या इसकी उप-धारा (2) के तहत बनाए गए जेजे नियम, 2007 के नियम 12 (3) (ए) (आई), (ii) और (iii) में उल्लिखित है।

जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94 प्रथम दृष्टया पर्याप्त होगी।

न्यायालय की प्रत्यक्ष संतुष्टि। उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर किशोरावस्था का अनुमान लगाया जा सकता है।

33.4 . यद्यपि उक्त अनुमान किशोरावस्था की आयु का निर्णायक प्रमाण नहीं है और इसका खंडन विपरीत पक्ष द्वारा दिए गए विपरीत साक्ष्य द्वारा किया जा सकता है।

33.5 . कि अदालत द्वारा जाँच की प्रक्रिया नहीं है

व्यक्ति की आयु घोषित करने के समान ही

जब मामला संबंधित आपराधिक अदालत के समक्ष मुकदमे के लिए लंबित है, तब किशोर की मांग जेजे बोर्ड के समक्ष की जाती है। जाँचक मामले न्यायालय प्रथम दृष्टिसँ दर्ज करैत अछि।

निष्कर्ष लेकिन जब उम्र का निर्धारण होता है

2015 के अधिनियम की धारा 94 की उप-धारा (2) के अनुसार, साक्ष्य के आधार पर एक घोषणा की जाती है। साथ ही जेजे बोर्ड द्वारा दर्ज की गई आयु को सही माना जाएगा।

उससे पहले लाए गए व्यक्ति की आयु। इस प्रकार, मानक

एक जांच में प्रमाण एक अयान चेतनराम चौधरी V में आवश्यक प्रमाण से अलग है।

महाराष्ट्र राज्य [अनिरुद्ध बोस, जे.]

कार्यवाही जहाँ किसी व्यक्ति की आयु का निर्धारण और घोषणा साक्ष्य के आधार पर की जानी है।

जाँच की जाती है और केवल तभी स्वीकार किया जाता है जब वे इसके योग्य हों। स्वीकृति।

33.6 . कि किसी व्यक्ति की आयु निर्धारित करने के लिए एक अमूर्त सूत्र निर्धारित करना न तो संभव है और न ही वांछनीय है। यह.

मामला। 33.7 . इस न्यायालय ने कहा है कि जब अभियुक्त की ओर से इस दलील के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है कि वह एक किशोर था, तो एक अति-तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए।

33.8 . यदि एक ही साक्ष्य पर दो विचार संभव हैं, तो अदालत को आरोपी को सीमावर्ती मामलों में किशोर ठहराने के पक्ष में झुकना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि जेजे अधिनियम, 2015 का लाभ कानून के साथ संघर्ष में किशोरों पर लागू किया जाए। साथ ही, अदालत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपराध करने के बाद सजा से बचने के लिए व्यक्तियों द्वारा जेजे अधिनियम, 2015 का दुरुपयोग न किया जाए

गंभीर अपराध।

33.9 . जब आयु का निर्धारण स्कूल के अभिलेख जैसे साक्ष्य के आधार पर किया जाता है, तो यह आवश्यक है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अनुसार इस पर विचार किया जाए, क्योंकि आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में रखे गए किसी भी सार्वजनिक या आधिकारिक दस्तावेज की निजी दस्तावेजों की तुलना में अधिक विश्वसनीयता होगी।

33.10 . कोई भी दस्तावेज जो सार्वजनिक दस्तावेजों के अनुरूप है, जैसे कि मैट्रिक प्रमाण पत्र, अदालत या जेजे बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते कि ऐसा सार्वजनिक दस्तावेज साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विश्वसनीय और प्रामाणिक हो। धारा 35 और अन्य प्रावधान।

33.11 . आयु निर्धारण के लिए ऑसिफिकेशन परीक्षण एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता है और किसी व्यक्ति की आयु के बारे में एक यांत्रिक दृष्टिकोण को केवल रेडियोलॉजिकल परीक्षा द्वारा चिकित्सा राय के आधार पर नहीं अपनाया जा सकता है। इस तरह के साक्ष्य निर्णायक साक्ष्य नहीं हैं बल्कि केवल एक बहुत ही उपयोगी मार्गदर्शक कारक [2023] 6 एस. सी. आर. हैं।

उल्लिखित दस्तावेजों के अभाव में विचार किया जाना

जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94 (2) में। ”

32. क्या जाँचकर्ता न्यायाधीश ने अपने निष्कर्ष देने में गलती की थी? जिन दस्तावेजों पर उन्होंने मुख्य रूप से भरोसा किया है, वे हैं स्कूल रजिस्टर, 30 जनवरी 2019 को स्कूल अधिकारियों द्वारा जारी निरनाराम की जन्म तिथि का प्रमाण पत्र और 15 अगस्त 2001 का स्थानांतरण प्रमाण पत्र। हालाँकि, बाद वाला स्थानांतरण का प्रमाण पत्र नहीं है जो निरनाराम के दूसरे स्कूल में स्थानांतरित होने को दर्शाता है, लेकिन इस प्रमाण पत्र में दर्ज है कि वह 15 मई 1989 को तीसरी कक्षा से चला गया था। फिर 19 सितंबर 2003 का अंदाराम का स्थानांतरण प्रमाण पत्र है जो 4 अप्रैल 1980 को अंदाराम की जन्म तिथि दर्शाता है। मुखराम के जाँच न्यायाधीश के सामने एक और स्थानांतरण प्रमाण पत्र था, लेकिन इसे जाँच न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया क्योंकि यह स्कूल के रिकॉर्ड के अनुरूप नहीं था। इन सभी

संरक्षक-माता-रजनी भाटी-बनाम-उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य [(2016) 12 एस. सी. सी. 744], 2000 के अधिनियम के तहत इसी तरह के प्रावधान के संबंध में यह रेखांकित किया गया है कि दस्तावेजों की विश्वसनीयता प्रथम दृष्टया प्रत्यक्ष जाँच होनी चाहिए। मनोज उर्फ मोनू उर्फ विशाल चौधरी-बनाम हरियाणा राज्य और एक अन्य [(2022) 6 एस. सी. सी. 187], रविंदर सिंह गोरखी (ऊपर) और बिराद मल सिंघवी (ऊपर) के मामलों में किशोर दावे को निर्धारित करने के लिए दस्तावेजों के विश्वसनीय होने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

नारायण चेतनराम चौधरी बनाम। महाराष्ट्र राज्य [अनिरुद्ध बोस, जे.]

33. जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, विचाराधीन विद्यालय एक सरकारी विद्यालय है। निरनाराम का "जन्म प्रमाण पत्र की तारीख" है

उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक के कार्यालय द्वारा जारी किया गया। यह प्रमाण पत्र राष्ट्रीय प्रतीक वाले राज्य सरकार के लेटरहेड पर जारी किया गया है। स्कूल के प्रधानाचार्य ने लिखित रूप में खुलासा किया है कि प्रवेश रजिस्टर की सामग्री सामान्य व्यवसाय में रखी जाती है। इसलिए, सामान्य रूप से उक्त रजिस्टर होगा 1872 के अधिनियम की धारा 35 में निर्दिष्ट परीक्षण को संतुष्ट करना, एक प्रासंगिक तथ्य होना। बिरादमल सिंघवी (उपरोक्त) का मामला चुनाव के संबंध में आयु प्रकटीकरण से संबंधित है न कि 2015 अधिनियम के तहत। उत्तरार्द्ध उन दस्तावेजों के बारे में अपनी धारा 94 के तहत एक दिशानिर्देश देता है जिन्हें स्वीकार किया जाएगा।

सबूत के रूप में। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र हमारे द्वारा सीधे स्वीकार नहीं किया गया है। वर्तमान आवेदन में, प्रवेश रजिस्टर से उद्धरण संलग्न किया गया है, जो स्वयं आवेदक के एक हलफनामे द्वारा समर्थित है। इसके अलावा, हमने 8 सितंबर 2022 को पारित अपने आदेश द्वारा मूल स्कूल प्रवेश रिकॉर्ड के लिए खुद को बुलाया था, जिसमें डॉ. मनीष सिंघवी से अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान राज्य से अनुरोध किया गया था कि वे इसका उत्पादन सुनिश्चित करें और उक्त रजिस्टर हमारे सामने प्रस्तुत किया गया था।

34. प्रवेश रजिस्टर की प्रामाणिकता या वास्तविकता के संबंध में, जो आवेदक की जन्म तिथि के प्रमाण पत्र का आधार है, श्री पाटिल का तर्क है कि पूरा रजिस्टर मनगढ़ंत था। बिनि।

नहीं। 423 यह है कि "उसका नाम हटा दिया गया था" जबकि प्रविष्टि सं। 562 , अभिलेख "पिछले अभिलेखों के अनुसार" है। यह स्पष्ट रूप से विद्यालय में पुनः प्रवेश या पुनः प्रवेश का मामला प्रतीत होता है। उनका आगे का रुख यह है कि पृष्ठों का अंतर्वेशन था। उन्होंने एक बार फिर कहा है कि

पृष्ठ (पृष्ठ सं। रजिस्टर के 33) को पीछे की ओर सिलवाया गया है। लेकिन ये निटपिक प्रस्तुतियाँ हैं और इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकती हैं कि [2023] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रवेश रजिस्टर अपने आप में नकली है। जहां तक निरनाराम के नाम का सवाल है, प्रवेश रजिस्टर में कोई विसंगति नहीं है। उनका क्रम संख्या 568 है जो उस क्रम में आता है जिसमें रजिस्टर को बनाए रखा जाता है और कुछ छोटे छात्रों को छोड़कर अन्य छात्रों की प्रवेश प्रविष्टियों के क्रम में होता है। अन्य प्रविष्टियों में नामों के संबंध में विसंगतियाँ। भले ही रजिस्टर को इस न्यायालय में भेजने के लिए नए सिरे से सिलवाया और पृष्ठांकित किया गया हो, वह होगा

इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि पूरी बात मनगढ़ंत है। इसके अलावा, यह प्रदर्शित करने के लिए कोई स्पष्ट सबूत नहीं है कि प्रारंभिक जांच के समय, रजिस्टर बिना सिलाई या बिना पृष्ठांकन के था। हमने स्वयं रजिस्टर देखा है और यह काफी पुराना है। इस प्रकार, हम जाँचकर्ता न्यायाधीश से सहमत हैं कि उसमें दर्ज जन्म तिथि मनगढ़ंत नहीं थी

प्रवेश।

35. अब आवेदक की अलग-अलग उम्र को दर्शाने वाली चार अन्य तिथियाँ हैं। पहला आरोप-पत्र में वह आयु है जिसके आधार पर उस पर मुकदमा चलाया गया है, दोषी ठहराया गया है और सजा सुनाई गई है, यानी 20 साल।

वर्ष 1994। लेकिन इस उम्र के प्रकटीकरण के स्रोत को पक्षों के विद्वान वकील द्वारा हमारे ध्यान में नहीं लाया गया है, सिवाय इसके कि आवेदक की उम्र उच्च न्यायालय के समक्ष उसके वकील द्वारा दी गई थी।

अपील सुनवाई। इसके बाद मतदाता सूची में दिखाई देने वाली आयु है और अगर कोई इसके अनुसार चलता है, तो अपराध के समय उसकी आयु 19 वर्ष होगी। 2 मार्च 2019 की पुलिस रिपोर्ट में मतदाता सूची का उल्लेख किया गया था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जांच न्यायाधीश द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया है। उनकी उम्र का तीसरा स्रोत पारिवारिक कार्ड है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि वे 1989 या 1991/1992 में 12 वर्ष के थे। यह उनके जन्म के वर्ष को 1977-79 तक ले गया होगा, और इससे अपराध के समय उनकी आयु 15 से 17 वर्ष हो जाएगी। जिन कारणों को हम पहले ही समझा चुके हैं, हमने बाद वाले दस्तावेज़ को त्याग दिया है। अब

हम किस दस्तावेज़ या स्रोत को स्वीकार करेंगे? पवन (उपरोक्त) के मामले में, इस अदालत की एक समन्वय पीठ ने किशोरता याचिका को खारिज कर दिया है, जब किशोरता की याचिका को उठाने के लिए दस्तावेज़ एकत्र किए गए थे।

दृढ़ विश्वास। उस फैसले में, इस अदालत ने मुरारी ठाकुर (ऊपर) के मामले का हवाला दिया और समन्वय पीठ ने कहा:

“ 41. सवाल यह है: क्या जाँच की जानी चाहिए या निचली अदालत से रिपोर्ट माँगी जानी चाहिए, जहां किशोरावस्था है।

इस न्यायालय के समक्ष पहली बार दावा किया गया। जहाँ अभियुक्त द्वारा इस न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री, प्रथम दृष्टया सुझाव देती है

यह कि अभियुक्त घटना की तारीख को 2000 के अधिनियम में परिभाषित "किशोर" था, रायन चेतनराम चौधरी बनाम को बुलाना आवश्यक हो सकता है।

महाराष्ट्र राज्य [अनिरुद्ध बोस, जे.]

रिपोर्ट या जाँच का आदेश दिया जाए। हालांकि, एक में मामला जहां किशोरता की याचिका बेईमान पाई जाती है या सामग्री में विश्वसनीयता की कमी होती है या विश्वास को प्रेरित नहीं करती है और

यहां तक कि, प्रथम दृष्टया, अदालत की संतुष्टि नहीं की जाती है, हमें नहीं लगता कि इस संबंध में आगे कोई अभ्यास आवश्यक है। यदि किशोरता की याचिका विचारण न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं उठाई गई थी और इस न्यायालय के समक्ष पहली बार उठाई गई थी, तो न्यायालय की न्यायिक अंतरात्मा को पर्याप्त और संतोषजनक सामग्री प्रस्तुत करके संतुष्ट किया जाना चाहिए कि अभियुक्त ने अपराध करने की तारीख को अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की थी; ऐसी सामग्री के बिना किशोरता की कोई और जांच अनावश्यक होगी। 42. जहां तक ए-2 का संबंध है, यह दिखाने के लिए दो दस्तावेजों पर भरोसा किया जाता है कि उन्होंने 25-9 2003/26-9-2003 पर अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की थी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपना बयान दर्ज करते समय निचली अदालत द्वारा उल्लिखित उनकी उम्र (17 वर्ष) शारीरिक आधार पर एक अस्थायी अवलोकन है।

उपस्थिति जो शायद ही उम्र का निर्धारण करती हो। दूसरे ने दस्तावेज द्वारा जारी स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र है

प्रधानाध्यापक, प्रेम शिक्षा निकेतन, बिलासपुर, रामपुर जो किसी भी विश्वास को प्रेरित नहीं करता है क्योंकि ऐसा लगता है कि इसे जारी किया गया है।

ए-2 के पहले ही दोषी ठहराए जाने के बाद 16-10-2006 पर। जन्म रजिस्टर से प्रविष्टि जैसे प्राथमिक साक्ष्य नहीं दिए गए हैं।

उत्पादित किया। हमें सलाहकार द्वारा भरोसा किए गए अनुलग्नक पी-3 (स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र) को स्वीकार करना मुश्किल लगता है। ए-1 के लिए,

रिकॉर्ड में रखा गया एकमात्र दस्तावेज एक स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र है जो उसकी दोषसिद्धि के बाद प्राप्त किया गया है। उनके मामले में भी जन्म रजिस्टर से प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई है। हम ऐसी सामग्री से प्रभावित या संतुष्ट नहीं हैं। कोई संतोषजनक और पर्याप्त सामग्री नहीं होने के कारण, प्रथम दृष्टया, हम ए-1 और ए की आयु के बारे में रिपोर्ट मांगने के लिए राजी नहीं हैं।

2 अपराध करने की तारीख को "।

36. जहाँ तक आवेदक के मामले का संबंध है, वर्तमान आवेदन में प्रकट किए गए परीक्षणों के आधार पर, 29 जनवरी 2019 को पारित एक आदेश में जांच का निर्देश दिया गया था। पवन (ऊपर) के मामले में एक स्कूल के हेडमास्टर द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र से अदालत को विश्वास नहीं हुआ। हालाँकि, यहाँ हमने कठोर प्रवेश पंजीकरण के लिए कहा है, जिसके आधार पर [2023] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जन्म दिया गया। उत्तराखण्ड 2015 अधिनियम की धारा 94 (2) (ए) (आई) के तहत निर्दिष्ट एक दस्तावेज है। अनुक्रम के क्रम में आयु प्रमाण को उपरोक्त प्रावधान के अनुसार साबित करने की आवश्यकता होती है, जन्म प्रमाण पत्र की तारीख उम्र के निर्धारण के लिए जांचा जाने वाला पहला दस्तावेज है। इस प्रकार, तथ्यात्मक रूप से उक्त निर्णय के अनुपात को अलग किया जा सकता है। पवन कुमार गुप्ता (उपरोक्त) के मामले में, किशोरता का दावा दूसरी बार उठाया गया था और इस कारण से यह माना गया था कि वही याचिका विचारणीय नहीं थी। मोहम्मद के मामले में एक समन्वय पीठा अनवर (ऊपर) ने कहा है कि देर से किए गए दावे न केवल साक्ष्य के उचित उत्पादन और अनुप्रयोग को रोकते हैं, बल्कि साक्ष्य को कमजोर भी करते हैं। रक्षा की वास्तविकता। लेकिन यह प्राधिकरण, कानून के एक पूर्ण प्रस्ताव के रूप में, यह निर्धारित नहीं करता है कि किसी अभियुक्त की किशोरता निर्धारित करने के लिए आयु प्रमाण के विलंबित उत्पादन की जांच नहीं की जा सकती है। इसके अलावा, 2015 के अधिनियम की धारा 9 (2) विशेष रूप से निर्धारित करती है कि इस तरह की याचिका को "किसी भी स्तर पर" उठाया जा सकता है। सूरजदेव महतो (उपरोक्त) के मामले का अनुपात भी इस मामले के तथ्यों में लागू नहीं होगा क्योंकि इस कार्यवाही में जांच न्यायाधीश ने इस सवाल पर गौर किया है कि क्या आवेदक द्वारा भरोसा किए गए प्रमाण पत्र उनके थे या नहीं और यह निष्कर्ष निकाला है कि निरनाराम वास्तव में नारायण थे। हमने इस निष्कर्ष का परीक्षण भी किया है और जांच करने वाले न्यायाधीश के विचार को कायम रखा है।

37. रामदेव चौहान (ऊपर) के मामलों में, संजीव कुमार गुप्ता-बनाम-उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य (2019) 12 एस. सी. सी.

आयु ", अनुभाग स्वयं यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि विद्यालय द्वारा जन्म प्रमाण पत्र की तिथि केवल अनुमान का कारण बनेगी। प्रावधान का तरीका 2015 के अधिनियम की धारा 94 की उप-धारा (2) के पहले दो उपखंडों में निर्दिष्ट दस्तावेजों को तैयार किया गया है, यदि प्राथमिकता के क्रम में स्थापित किया जाता है, तो अपराध करने की तारीख को नाबालिग होने का दावा करने वाले आरोपी या दोषी की उम्र निर्धारित करने के लिए उसमें दर्शाई गई तारीखों को स्वीकार करना होगा।

इस घटना में दस्तावेज़ नारायण चेतनराम चौधरी v. महाराष्ट्र राज्य [अनिरुद्ध बोस, जे.]

धारा 94 (2) (i) में निर्दिष्ट है कि जांच निकाय को उसके उपखंड (ii) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। एकमात्र चेतावनी, जो इसमें निहित है, जो इसके कई निर्णयों से सामने आई है।

अदालत, यह है कि दस्तावेज़ को विश्वास को प्रेरित करना चाहिए। लेकिन आयु-निर्धारक प्राधिकरण की प्रेरणा की कमी किसी ठोस कारण से आनी चाहिए और किशोर-दावेदार की आयु के बारे में ऐसे निकाय की अपनी धारणा से स्रोत नहीं होना चाहिए।

38. प्रताप सिंह बनाम झारखंड राज्य और एक अन्य [(2005) 3 एस. सी. सी. 551] के मामले में एक संविधान पीठ

1986 के अधिनियम और 2000 के अधिनियम के तहत किशोर का अर्थ अभिनिर्धारित किया गया:

“ 12. 2000 के अधिनियम की धारा 2 के खंड (1) में "कानून के साथ संघर्ष में किशोर" को परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है एक किशोर जिस पर अपराध करने का आरोप है। 1986 के अधिनियम और 2000 के अधिनियम की परिभाषाओं के बीच उल्लेखनीय अंतर यह है कि 1986 के अधिनियम में "कानून के साथ संघर्ष में किशोर" अनुपस्थित है। 1986 के अधिनियम में अपराधी किशोर की परिभाषा जैसा कि देखा गया है ऊपर एक अपराध के लिए संदर्भित है जिसे उसके द्वारा किया गया कहा जाता है। यह अपराध की तारीख है जब वह कानून के साथ टकराव में था। जब एक किशोर को सक्षम व्यक्ति के सामने पेश किया जाता है

प्राधिकरण और/या अदालत ने उस तारीख को कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन उसे कथित अपराध के लिए प्राधिकरण के सामने लाया गया था जो उसने किया था।

इसलिए, हमारे विचार में, 1986 के अधिनियम में क्या निहित था

2000 के अधिनियम में स्पष्ट किया गया है। ”

39. एक बाद के निर्णय में, जितेंद्र सिंह उर्फ बब्बू सिंह और एक अन्य-बनाम-उत्तर प्रदेश राज्य [(2013) 11 एससीसी 193] के मामले में,

इस न्यायालय का दृष्टिकोण निम्नलिखित अंश में परिलक्षित हुआ:

“ 72. उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह है कि अपराध करने की तारीख को अपीलार्थी की आयु 16 वर्ष से अधिक थी, लेकिन वह निश्चित रूप से 18 वर्ष से कम आयु का था।

और इसलिए 2000 के अधिनियम के लाभ का हकदार है, चाहे बाद का अधिनियम घटना की तारीख को कानून पुस्तिका में क्यों न हो। कठिनाई तब उत्पन्न होती है जब हम इस बात की जांच करते हैं कि क्या अपीलार्थी के मुकदमे और दोषसिद्धि के परिणामी आदेश को भी अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना अलग रखा जाना चाहिए। हालाँकि दोषसिद्धि को दरकिनार नहीं किया जा सकता है क्योंकि

एक से अधिक कारण:

आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

72.1 . सबसे पहले, क्योंकि इस मामले में निचली अदालतों द्वारा दर्ज किए गए दोषसिद्धि के आदेश को उच्च न्यायालय या हमारे समक्ष कोई चुनौती नहीं थी और न ही है। वास्तव में इस न्यायालय के समक्ष एक अतिरिक्त आधार के माध्यम से किशोरता की याचिका अपीलार्थी की दोषसिद्धि को इस आधार पर चुनौती देने से कम रही कि संबंधित न्यायालय को अपीलार्थी पर मुकदमा चलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

72.2 . दूसरा, क्योंकि मामले में तथ्य की स्थिति यह है कि घटना की तारीख यानी 24-5 1988 को अपीलार्थी की आयु 16 वर्ष से अधिक थी। इसलिए वह 1986 के अधिनियम के तहत किशोर नहीं था।

उस समय क्षेत्र, और न ही 1986 का अधिनियम निचली अदालत को अपीलार्थी पर उस अपराध के लिए मुकदमा चलाने के अपने अधिकार क्षेत्र से वंचित करता है जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया था। 2000 के अधिनियम द्वारा 1986 के अधिनियम को निरस्त करने से किशोरावस्था की आयु बढ़कर 18 वर्ष हो गई।

संसद ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 20 को अधिनियमित करके ऐसे मामलों के लिए प्रावधान किया जो या तो विचाराधीन थे या मुकदमे के समापन के बाद, अपीलार्थी या पुनरीक्षण अदालत के समक्ष लंबित थे, जो निम्नलिखित प्रभाव से हैं:

" 20.लंबित मामलों के संबंध में विशेष प्रावधान। इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, सभी

जिस तारीख को यह अधिनियम उस क्षेत्र में लागू होता है, उस तारीख को किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में लंबित किशोर के संबंध में कार्यवाही उस अदालत में जारी रखी जाएगी जैसे कि यह अधिनियम पारित नहीं किया गया था और यदि अदालत को पता चलता है कि किशोर ने कोई अपराध किया है, तो वह इस तरह के निष्कर्ष को दर्ज करेगी और इसमें कोई सजा देने के बजाय

किशोर के संबंध में, किशोर को बोर्ड के पास भेजें जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उस किशोर के संबंध में आदेश पारित करेगा जैसे कि इस अधिनियम के तहत जांच पर यह संतुष्ट हो गया था कि एक किशोर

अपराध किया है:

बशर्ते कि बोर्ड, आदेश में उल्लिखित किसी भी पर्याप्त और विशेष कारण के लिए, मामले की समीक्षा कर सकता है और ऐसे लोगों के हित में उचित आदेश पारित कर सकता है।

किशोर।

नारायण चेतनराम चौधरी बनाम। महाराष्ट्र राज्य [अनिरुद्ध बोस, जे.]

स्पष्टीकरण। किसी भी न्यायालय में कानून के साथ संघर्ष में किशोर के संबंध में मुकदमे, संशोधन, अपील या किसी अन्य आपराधिक कार्यवाही सहित सभी लंबित मामलों में, ऐसे किशोर की किशोरता का निर्धारण

धारा 2 के खंड (1) के संदर्भ में, भले ही किशोर इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उससे पहले ऐसा करना बंद कर दे और इस अधिनियम के प्रावधान इस तरह लागू होंगे जैसे कि उक्त प्रावधान सभी उद्देश्यों के लिए और सभी भौतिक समय पर लागू थे जब कथित अपराध किया गया था। प्रतिबद्ध "।

धरमवीर-बनाम-राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) और एक अन्य [(2010) 5 एस. सी. सी. 344] और महेश जोगी-बनाम-राजस्थान राज्य [(2014) 15

एस. सी. सी. 184], इसी तरह का दृष्टिकोण इस न्यायालय द्वारा लिया गया है। सत्य देव उर्फ भूरे-बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(2020) 10 एस. सी. सी. 555] मामले में, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि 2015 के अधिनियम की धारा 25 के साथ पठित सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के आलोक में, एक आरोपी को अपराध करने के समय 18 वर्ष से कम आयु के किशोर के रूप में माने जाने के उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। न्यायालय का तर्क था कि इस तरह का अधिकार 2000 अधिनियम के तहत अर्जित और फलीभूत किया गया था, भले ही अपराध 1 अप्रैल 2001 को 2000 अधिनियम के प्रवर्तन से पहले किया गया था।

40. जहाँ तक आवेदक का संबंध है, स्कूल प्रमाण पत्र में उसकी जन्म तिथि के आधार पर किशोरता का उसका दावा 1986 के अधिनियम, 2000 अधिनियम या 2015 के अधिनियम के तहत किशोर, "कानून के साथ संघर्ष में किशोर" या "कानून के साथ संघर्ष में बच्चे" की परिभाषाओं के आधार पर भिन्न नहीं होगा। किशोरावस्था या बच्चा होने के उसके दावे को निर्धारित करने की प्रक्रिया को लागू करने के लिए, हमारी राय में, संबंधित वैधानिक निकाय द्वारा उस अभ्यास को करने के समय लागू कानून प्रबल होगा। इसलिए, उनके मामले में, हमने 2015 के अधिनियम की धारा 94 के साथ पठित धारा 9 के प्रावधानों के आधार पर उनके दावे का परीक्षण किया है।

41. 2015 के अधिनियम के तहत किशोरावस्था के निर्धारण के लिए जन्म प्रमाण पत्र की तारीख मुख्य कारक होनी चाहिए। ऋषिपाल के मामले में

सिंह सोलंकी (ऊपर), इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने निर्धारित किया है

यह सिद्धांत कि 2015 अधिनियम की धारा 9 (2) के तहत शुरू की गई जांच उसकी धारा 94 में निहित जांच के समान होगी। हम इस विचार को स्वीकार करते हैं। हमने जन्म तिथि प्रमाण पत्र के स्रोत की मांग की है, जिसमें स्कूल में प्रवेश के समय आवेदक की जन्म तिथि दर्ज की गई है जो वर्ष 1986 में थी। जहाँ तक [2023] 6 एस. सी. आर. की असंगत तिथियाँ हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अन्य दस्तावेजों में उल्लिखित जन्म, उनमें से किसी को भी निर्दिष्ट नहीं किया गया है

उक्त कानून की धारा 94 (2) में निर्धारित आयु निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए विचार में लिया गया। एक बार जब आवेदक स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके किशोरावस्था के अपने दावे के समर्थन में अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है, तो राज्य को यह दिखाने के लिए कोई भी सम्मोहक विरोधाभासी सबूत पेश करना पड़ता है कि उसका रिकॉर्ड प्रवेश रजिस्टर में जन्म तिथि गलत थी। इस मामले में राज्य ने ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं दिया है जो इस तरह के प्रमाण पत्र को अविश्वसनीय या गलत साबित करे। राज्य और शिकायतकर्ता ने मतदाता सूची के अलावा केवल उसके द्वारा प्रकट की गई सामग्री के आधार पर आवेदक के मामले को गलत साबित करने की मांग की है। यहाँ, हम स्कूल रजिस्टर में प्रविष्टि पर संदेह करने के लिए किसी भी अनुमान में शामिल नहीं हो सकते हैं। आवेदक की उम्र के आधार का खंडन करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया है।

अपराध विज्ञान जांच न्यायाधीश की रिपोर्ट की जांच करते समय इस कारक को ध्यान में रखना। इसके अलावा, अस्थिकरण परीक्षण में प्रकट आवेदक की आयु आवेदक की आयु को, जैसा कि उसने दावा किया है, रिपोर्ट में निर्दिष्ट सीमा के भीतर रखती है। उक्त परीक्षण वर्ष 2005 में आयोजित किया गया था, और उनकी आयु 22 से 40 वर्ष की सीमा में निर्धारित की गई थी। अगर हम 2005 में उनकी उम्र को 22 वर्ष के रूप में लेते हैं, तो उनका जन्म वर्ष 1983 होता। यह मोटे तौर पर प्रवेश रजिस्टर में निहित जन्म तिथि के अनुरूप होगा।

42. ऋषिपाल सिंह सोलंकी (उपरोक्त) के मामले में यह निर्धारित किया गया है कि यदि एक ही साक्ष्य पर दो विचार संभव हैं तो अदालत को आरोपी को सीमावर्ती मामलों में किशोर ठहराने के पक्ष में झुकना चाहिए। जम्मू और कश्मीर राज्य (अब जम्मू और कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश) और अन्य-बनाम-शुभम संगरा [2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1592] के मामले में, पराग भाटी (उपरोक्त) के निर्णय का पालन किया गया, जिसमें कहा गया था कि 2000 के अधिनियम के लाभ केवल ऐसे मामलों में दिए जाने चाहिए जिनमें आरोपी को स्पष्ट और स्पष्ट मामले के आधार पर किशोर माना जाता है कि आरोपी घटना की तारीख को नाबालिग था और दस्तावेजी साक्ष्य कम से कम प्रथम दृष्टया उसके अल्पसंख्यक होने के बारे में विश्वास को प्रेरित करते हैं। इस निर्णय में यह राय दी गई थी कि जब कोई अभियुक्त गंभीर और जघन्य अपराध करता है, तो उसकी नारायण चेतनराम चौधरी बनाम की याचिका।

महाराष्ट्र राज्य [अनिरुद्ध बोस, जे.]

किशोरावस्था को उसके बचाव में आने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और अदालत उसके अल्पमत का निर्धारण करने में एक आकस्मिक या घुड़सवार दृष्टिकोण नहीं अपना सकती है। ऋषिपाल सिंह सोलंकी (उपरोक्त) के मामले में कुछ अलग दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है, जिसका हमने ऊपर उल्लेख किया है। ऋषिपाल सिंह सोलंकी (ऊपर) में लिए गए दृष्टिकोण के समान एक निर्णय में परिलक्षित हुआ

दो-राजिंदर चंद्र बनाम के मामले में इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ

छत्तीसगढ़ राज्य और दूसरा [(2002) 2 एस. सी. सी. 287]। तथापि, हमारी राय में, यदि न्यायालय, बोर्ड या समिति संतुष्ट होती है कि अपराध की तिथि पर दावेदार किशोर था, तो अपराध की गंभीरता के आयाम पर न्यायालय द्वारा 2015 के अधिनियम के तहत किसी अभियुक्त या दोषी को दिए गए लाभ को अस्वीकार करने के लिए विचार नहीं किया जा सकता है। हम शुभम संगरा (ऊपर) और पराग भाटी (ऊपर) के मामलों में की गई टिप्पणियों से सहमत हैं कि अभियुक्त या दोषी की आयु निर्धारित करने में किशोरावस्था की याचिका पर एक आकस्मिक या घुड़सवार दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए, लेकिन किशोरता के निर्धारण के खिलाफ निर्णय केवल इस कारण से नहीं लिया जाना चाहिए कि अपराध शामिल है जो जघन्य या गंभीर है। अपराध की डिग्री या आयाम को किसी अभियुक्त (इस मामले में एक दोषी) की किशोरता की जांच में न्यायालय के दृष्टिकोण को निर्देशित नहीं करना चाहिए। अपवाद जहाँ एक अलग दृष्टिकोण लिया जा सकता है, प्रदान किया गया है।

स्वयं विधानमंडल द्वारा 2015 के अधिनियम की धारा 15 में और यदि जघन्य अपराध के आधार पर, एक किशोर को 2015 के अधिनियम के लाभ से वंचित किया जाना आवश्यक है, तो उसमें निर्दिष्ट पाठ्यक्रम का पालन करना आवश्यक होगा।

43. हमारे निष्कर्षों और इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हमने ऊपर बताए गए कारणों के आलोक में, हम जांच की रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं।

न्यायाधीश। हम घोषणा करते हैं कि आवेदक की जन्म तिथि राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक द्वारा जारी प्रमाण पत्र में परिलक्षित होती है।

विद्यालय, जलन्सार, तहसील-श्री डूंगरगढ़, जिला-बीकानेर, दिनांक 30 जनवरी 2019, जिसकी एक प्रति जांच में संलग्न की गई है।

"आई-2" के रूप में रिपोर्ट को उस अपराध के करने के समय उसकी उम्र निर्धारित करने के लिए स्वीकार किया जाना है जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया है। गुज़र रहा है। उस प्रमाण पत्र के अनुसार अपराध करने के समय उनकी आयु 12 वर्ष और 6 महीने थी। इस प्रकार, वह 2015 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपराध करने की तारीख को एक बच्चा/किशोर था, जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया है। यह निरन्तराम की वास्तविक आयु मानी जाएगी, जिन पर नारायण के रूप में मुकदमा चलाया गया और उन्हें दोषी ठहराया गया। वह पहले ही 3 साल से अधिक की कारावास की सजा काट चुका है और कानून के तहत जैसा कि अपराध के समय प्रचलित था और 2015 के अधिनियम के तहत भी, उसे मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है। इस खोज को देखते हुए, [2023] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1994 के सत्र मामला संख्या 462 में पुणे के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा उन्हें मौत की सजा सुनाने का आदेश पारित किया गया और बाद में उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई, कानून के संचालन द्वारा अमान्य हो जाएगा। 2015 के अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उसे सुधार गृह से तुरंत रिहा कर दिया जाएगा, जिसमें वह कैद है, क्योंकि उसने 28 साल से अधिक का कारावास झेला है। 1986 के अधिनियम की धारा 21 में भी काफी हद तक यही प्रावधान था।

अधिकतम सजा के प्रश्न पर जो किशोर न्यायालय द्वारा अपराधी किशोर को दी जा सकती है। निरोध की अवधि पर प्रतिबंध जो बोर्ड द्वारा 2015 के अधिनियम के तहत 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को दिया जा सकता है, उस न्यायालय पर भी लागू होगा जिसके समक्ष किशोरता का प्रश्न निर्धारित किया जा रहा है।

44. 2016 का आई. ए. सं. 5242 और 2016 का आई. ए. सं. 5245 भी पुनरीक्षण याचिका को फिर से खोलने के लिए आवेदक द्वारा लिए गए आवेदन हैं। हालाँकि, हमारा विचार है कि 2015 के अधिनियम की धारा 9 (2) के तहत एक आवेदन एक स्वतंत्र कार्यवाही है और हमने तय किया है कि समीक्षा आदेश पर फिर से विचार किए बिना। सीआरएल। हस्तक्षेपकर्ता द्वारा जाँच रिपोर्ट पर आपत्ति उठाते हुए 2019 का एम. पी. सं. 155609 दायर किया गया है।

हम उसी का निपटारा करते हैं क्योंकि हमने इस याचिका की सामग्री पर विचार किया है। अन्य सभी आवेदनों का निपटारा कर दिया जाएगा।

45. वर्तमान आवेदन की उपरोक्त शर्तों में अनुमति है।

आवेदन

की अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान

(सहायक: आरश चौधरी और प्रेरणा दीप, एलसीआरएएस)